सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

परिवहन विशेष

www.newsparivahan.com

वर्ष 01, अंक 342, नई दिल्ली । मंगलवार, 20 फरवरी 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

100 बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है।

03 अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने किए रामलला के दर्शन

06 लॉजिस्टिक लागत घटने का परिदृश्य

08 विधानसभा अध्यक्ष का भीलवाड़ा आगमन पर भाजपा ने किया स्वागत,

संक्षेप

गुरुग्राम में वाहन चालक 10 हजार के चालान से बच सकते हैं, बस न करें ये लापरवाही

गुरुग्राम। गुरुग्राम में अब ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना (फाइन) लगा सकती है, अगर वो एंबुलेंस, अग्निशमक वाहन को निकलने के लिए रास्ता नहीं देते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। यह पुलिस इसी सप्ताह से जुर्माना लगाएगी। डीसीपी (ट्रैफिक) वीरेंद्र विज ने कहा कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जोनल अधिकारी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे। डीसीपी ने कहा कि जो अपराधी एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं, उन्हें बिना किसी देरी के ऑनलाइन चालान मिलेगा। उन्होंने कहा कि घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ चालान जारी किए जाएंगे। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के तहत अपराध के लिए चालान राशि 10,000 रुपये है। इससे गंभीर स्थिति में एंबुलेंस में विभिन्न अस्पतालों में जाने वाले लोगों को बचाने में मदद मिलेगी। डीसीपी विज ने कहा कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस पहले से ही विभिन्न अस्पतालों में प्रत्यारोपण के लिए अंगों को ले जाने वाली एंबुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रदान कर रही है और गंभीर रोगियों की जान बचाने में मदद कर रही है।

आखिर क्यों प्रवर्तन शाखा गलत चलने वाले ई-रिक्शों पर कार्यवाही नहीं करते ?

संजय बाटला

नई दिल्ली।

1. दिल्ली की सड़को पर गलत तरीके से चलने वाले ई रिक्शों,
2. बिना पंजीकरण नम्बर प्राप्त किए दिल्ली की सड़को पर चलने वाले ई रिक्शों,
3. बिना फिटनेस लिए दिल्ली की सड़को पर चलने वाले ई रिक्शों,
4. बिना इंश्योरेंस पॉलिसी लिए दिल्ली की सड़को पर चलने वाले ई रिक्शों,
5. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चालको द्वारा दिल्ली की सड़को पर चलने वाले ई रिक्शों,
6. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित सड़को पर चलने वाले ई रिक्शों और
7. सड़को पर जाम लगाने वाले ई रिक्शों पर आखिर दिल्ली **परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा के आला अधिकारी एवम विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम क्यों कार्यवाही करने के आदेश पारित नही करते ? और क्यों प्रवर्तन शाखा के अधिकारी और कर्मचारी भी आखों से सब कुछ देखते हुए भी आंखे बंद रख इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं करते, क्या है इसके पीछे छुपा कारण, बड़ा सवाल ?**

क्या दिल्ली की जनता की सुरक्षा के प्रति प्रवर्तन शाखा के आला अधिकारी, निम्न अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ भी लेना देना नहीं, बड़ा सवाल ?

क्या प्रवर्तन शाखा के आला अधिकारी के लिए दिल्ली की जनता के समय सीमा समाप्त कर चुके वाहनों को उठवा कर अपने प्रिय वाहन स्क्रैप डीलर को सुपुर्द करवाना ही था या जनता की सुरक्षा के प्रति भी उनका कोई दायित्व बनता है, बड़ा सवाल ?

जल्द शुरू हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेस-वे, आचार संहिता लागू होने से पहले पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार द्वारका एक्सप्रेस-वे (Dwarka Expressway) के गुरुग्राम भाग का शुभारंभ करेंगे। इसे ध्यान में रखकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने तैयारी तेज कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि दो से चार दिन में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आ जाएगा। द्वारका एक्सप्रेस-वे के आसपास ही कहीं समारोह रखा जाएगा।

गुरुग्राम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार द्वारका एक्सप्रेस-वे के गुरुग्राम भाग का शुभारंभ करेंगे। इसे ध्यान में रखकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने तैयारी तेज कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि दो से चार दिन में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आ जाएगा।

द्वारका एक्सप्रेस-वे के आसपास ही कहीं समारोह रखा जाएगा, ताकि अचानक रोड शो का कार्यक्रम बनने पर तैयारी में कमी न रहे। गुरुग्राम भाग के जल्द ही शुभारंभ होने की चर्चा से इलाके में खुशी का माहौल है।

पिछले एक साल से लागू है गुरुग्राम भाग

पिछले एक साल से द्वारका एक्सप्रेस-वे का गुरुग्राम भाग तैयार है। एनएचएआइ का प्रयास था कि गुरुग्राम एवं दिल्ली भाग एक साथ ही चालू हो, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। लोगों की परेशानी को देखते हुए गुरुग्राम भाग को चालू कराने का निर्णय लिया गया है।

आचार संहिता लागू होने से पहले शुभारंभ

चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले गुरुग्राम भाग का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेस-वे के रंग-रोगन से लेकर साफ-सफाई का काम दिन-रात किया जा रहा है। एनएचएआई के अधिकारी प्रतिदिन तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी न रहे, यह मौके पर जाकर देख रहे हैं।

दिन-रात तैयारी चल रही

रविवार को भी एनएचएआई के अधिकारी तैयारी में जुटे रहे। तारीख तय होते ही अफरा-तफरी की स्थिति न बने, इसे ध्यान में रखकर ही दिन-रात तैयारी चल रही है। इधर, गुरुग्राम भाग के किसी भी दिन चालू होने की चर्चा से इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। सभी प्रधानमंत्री को नजदीक से देखना चाहते हैं।

आना-जाना हो जाएगा आसान

गांव दौलताबाद निवासी रमेश कुमार, लाला एवं महेंद्र सिंह कहते हैं कि प्रोजेक्ट पूरा होते ही इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। किसी भी इलाके में कुछ ही समय में पहुंचना आसान हो जाएगा। न दिल्ली दूर लगेगी और न ही गुरुग्राम के अन्य इलाके। पालम विहार निवासी हरमेश मल्होत्रा कहते हैं कि गुरुग्राम के विकास में द्वारका एक्सप्रेस-वे मील का पत्थर साबित होगा।

ट्रैफिक के दबाव की वजह से गुरुग्राम के कुछ इलाके अभी काफी पीछे हैं। इन इलाकों में विकास के पंख लगेंगे। बता दें कि दिल्ली भाग में टनल का काम बाकी है। इसे देखते हुए दिल्ली भाग का विधिवत शुभारंभ न करके टनल के साइड से ट्रैफिक चलाने पर विचार किया जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिले।

नौ हजार करोड़ रुपये की लागत का है प्रोजेक्ट

दिल्ली के महिपालपुर में शिवमूर्ति के नजदीक से लेकर गुरुग्राम में खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक नौ हजार करोड़ रुपये की लागत से द्वारका एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेस-वे का 18.9 किलोमीटर हिस्सा गुरुग्राम में जबकि 10.1 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में पड़ता है।

दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर, केजरीवाल ने मेट्रो से जुड़ा लिया ये फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली मेट्रो कई साल से अटकी दिल्ली मेट्रो के फेज चार लाइन की राह का रोड़ा खत्म हो गया है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एमओयू साइन करने को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली के लाखों लोगों को फायदा होगा। बता दें कि 47 किलोमीटर के इस फेज में 39 मेट्रो स्टेशन होंगे।

नई दिल्ली। कई साल से अटकी दिल्ली मेट्रो के फेज चार लाइन की राह का रोड़ा खत्म हो गया है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एमओयू साइन करने को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली के लाखों लोगों को फायदा होगा।

बता दें कि 47 किलोमीटर के इस फेज में 39 मेट्रो स्टेशन होंगे। रिठाला, बवाना, नरेला और कोंडली कॉरिडोर को मंजूरी दी गई, इंद्रलोक, इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर और लाजपत नगर और साकेत जी ब्लाक कॉरिडोर को भी मंजूरी दे दी गई है।

दिल्ली आने-जाने वालों को बड़ी राहत, 3 रास्ते और खुले; किसान आंदोलन के चलते सील हुए थे बॉर्डर

पहले दिल्ली आने-जाने वाले सभी रास्ते बंद होने से उद्योगपति कुंडली और राई औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रियों में नहीं आ जा पा रहे थे। हालांकि अब दिल्ली से आवागन के लिए तीन लिंक रोड खोल दिए गए हैं। वहीं कुंडली बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मियों और अर्ध सैनिक बलों के जवानों को शिफ्टों में आराम दिया जा रहा है।

परिवहन विशेष न्यूज

सोनीपत/नई दिल्ली। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सोनीपत की दिल्ली से लगती सभी सीमाएं सील होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब दिल्ली से आवागन के लिए तीन लिंक रोड खोल दिए गए हैं। इससे उद्योगपतियों और कारोबारियों को राहत मिली है, क्योंकि पहले सभी रास्ते बंद होने से उद्योगपति कुंडली और राई औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रियों में नहीं आ जा पा रहे थे।

वहीं कुंडली बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मियों और अर्ध सैनिक बलों के जवानों को शिफ्टों में आराम दिया जा रहा है। एक टुकड़ी मुस्तैद रहती है तो दूसरी को बॉर्डर पर ही सुस्ताने के लिए कहा जाता है। जवान सड़क पर बैठकर ही ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर तक करते हैं। कई जवान या अधिकारी अपनी गाड़ियों में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जवान खुद ही बर्तन साफ करते हैं। होटलों और ढाबों से खुला या पैक्ड खाना उन्हें सर्व किया जाता है।

यह लिंक रोड आज खुले

कुंडली-प्याऊमनियारी से नरेला और सिंघु गांव होते हुए दिल्ली

नाहरा-नाहरी से गुजर रही डबल नहरों के बीच के रोड से होते हुए बवाना से दिल्ली

रविवार को यह मार्ग खोले गए थे

बीसवां मील, अकबरपुर बारोटा, सफियाबाद होते नरेला

नाहरा-नाहरी से लामपुर बार्डर होते हुए नरेला आ जा सकते हैं

एनएच-44 पर कुंडली थाने के सामने से गांव दहिसरा होते हुए दिल्ली

किसानों को रोकने के लिए इंतजाम पूरे

कुंडली बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली कूच रोकने के लिए सात लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सड़क पर पहले बैरिकेडिंग, फिर कंक्रीट की दीवार, फिर लोहे के बैरिकेड, फिर कंटीले तारों की बाड़, फिर कंडम वाहनों और कंटेनरों के गतिरोध बनाए गए हैं। इसके बाद सड़क पर ही जवानों और अधिकारियों के लिए टेंट लगाए गए हैं।

बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के तीन हजार से अधिक जवान और अर्ध सैनिक बलों की दो कंपनियां तैनात की गई है। इनमें एक महिला जवानों की टुकड़ी भी शामिल है। पैरा मिलिट्री और पुलिस जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात है। अब इन्हें शिफ्टों में तैनात किया जा रहा है और शिफ्टों में ही आराम दिया जा रहा है। एक टुकड़ी तैनात रहती है तो दूसरी वहीं सड़क पर आराम करती है।

सड़क पर ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर

पैरा मिलिट्री और पुलिस के जवान सड़क पर ही ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर कर रहे हैं। होटलों और ढाबों से बड़े बर्तनों में या पैक्ड फूड इन्हें सर्व किया जा रहा है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली एयरपोर्ट से विमान नोएडा-हिंडन होंगें शिफ्ट

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। दिल्ली के सबसे व्यस्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर विमानों-यात्रीयों के बढते बोझ को कम करने की कवायद शुरू हो गई है।दिल्ली एयरपोर्ट को संभालने वाली संस्था (जीएमआर) एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बडे विमान के साथ सेवाए देने वाली फुल टाइम एयरलाइन लो कास्ट एयरलाइन (एलसीए) जेवर स्थित नोएडा इंटरनैशनल एयरपोर्ट और गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट में शिफ्ट करने की योजना है।

उल्लेखनीय है कि फिलहाल दिल्ली के (आईजीआई) एयरपोर्ट से प्रति सप्ताह 8,554 फ्लाइट्स संचालन होती है।इसमें से सबसे ज्यादा3,892 यानि 38.5% हिस्सेदारी एलसीए (इंडिगो एयरलाइन) की है। इस बावत जीएमआर के कार्यकारी निदेशक सौरभ चावला ने कुछ दिन पहले बताया था कि जेवर एयरपोर्ट पर फोकस मुख्य रूप से लो कोस्ट एयरलाइन (एलसीए) पर ही होगा।

सौरभ चावला का कहना है कि लो कोस्ट एयरलाइन कं.अपना परिचालन दिल्ली हवाई अड्डे से जेवर / हिंडन हवाई अड्डे या अन्य क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर शिफ्ट करेंगें।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन जहां जीएमआर,समूह करता है,वहीं जेवर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का काम यमुना इंटरनैशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड कर रहा है।जेवर एयरपोर्ट से हवाई संचालन इस साल के अंत तक शुरू हो सकता है। वहीं हिंडन एयरपोर्ट का संचालन सरकार का एयरपोर्ट अथॉरटी ऑफ इंडिया करता है। वर्तमान में जेवर एयरपोर्ट से स्टार एयर जैसी क्षेत्रीय एयरलाइंस का संचालन हो रहा है।

इस वक्त (आईजीआई) एयरपोर्ट से 5 प्राईवेट एयरलाइंस के विमान है। इनमें इंडिगो एलसीए, की 3,292 फ्लाइट्स, यानि 38.5%की हिस्सेदारी एयर इंडिया की 1618- 18.9%,विस्तारा की 1270- 14.8% स्पाइसजेट 581- 6.8% तथा एआईएक्स कनेक्ट एलसीए 518-61% की हिस्सेदारी है। अब इन एयरलाइंस को जेवर भेजने का मकसद ।दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर हैवी ट्रेफिक दबाव है।वहीं सस्ती एयरलाइंस के लिए नोएडा ज्यादा बेहतर है। इसकी वजह कि दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान ईंधन पर 25%वैल्यू एकेडमिक टैक्स (वैटस) लगता है।जबकि नो एडा एयरपोर्ट पर केवल 4 % ही लगता है।विमान परिचालन की 40%लागत ईंधन की होती है।जाहिर है कि वैट कम लगने की वजह से टिकट के दाम भी कम होने की संभावना है।इस फैसले से दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार बढ रहे ट्रेफिक को भी कम करने में कामयाबी मिलेगी।

इनसाइड

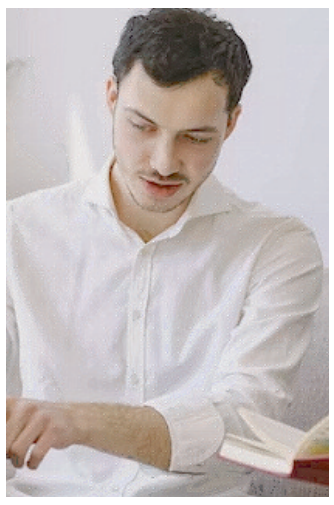

ऑफिस में महिला कलीग से बात करें तो जरूर रखें इन बातों का ख्याल, बन जाएंगे उनके फेवरेट, बॉन्डिंग भी होगी स्ट्रॉन्ग

ऑफिस में फीमेल कलीग से बात करना कई पुरुषों के लिए आसान नहीं होता है. ऐसे में पुरुष महिला कलीग के सामने भाषा पर ध्यान देने से लेकर स्माइल करने, मोटिवेट रखने जैसे कुछ टिप्स अपनाकर उनके साथ हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं.

ऑफिस में पुरुष और महिला कलीग्स दोनों मौजूद रहते हैं. ऐसे में कई मेल कलीग्स आपस में काफी अच्छे दोस्त होते हैं मगर फीमेल कलीग्स के सामने ज्यादातर पुरुष असहज महसूस करते हैं. आप चाहें तो महिला सहकर्मी से बात करते समय कुछ चीजों का खास ख्याल रखकर ना सिर्फ उनके फेवरेट बन सकते हैं, बल्कि उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं.

फीमेल कलीग के सामने कई सारे पुरुष नर्वस हो जाते हैं, जिसके चलते वे महिलाओं से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं. इसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है. ऐसे में कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप फीमेल कलीग्स से बेस्ट बॉन्डिंग बना सकते हैं. आइए जानते हैं ऑफिस में महिला कलीग से बात करने के टिप्स.

भाषा पर संयम रखें

अपने ऑफिस की किसी भी महिला कर्मचारी से बात करते समय पुरुषों को भाषा पर ध्यान देना जरूरी होता है. दरअसल, पुरुष आपस में तुम या तू करके बात करते हैं मगर महिलाओं के सामने ऐसे पेश आने से आपका इम्प्रेशन खराब हो सकता है. वहीं, फीमेल कलीग के सामने बॉडी लैंग्वेज भी सही रखें, जिससे वे भी आपके सामने सहज महसूस कर सकें.

स्माइल करना है जरूरी

अगर आप महिला कलीग से बात करने में असहज महसूस करते हैं तो आप उन्हें दूर से देखकर मुस्कुरा भी सकते हैं. फीमेल कलीग से आई कॉन्टैक्ट होने पर आपकी एक मुस्कान भी काफी है. इससे आप बिना बोले उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकेंगे और आपका रिश्ता मजबूत होने लगेगा.

काम पर ध्यान दें

महिला कलीग से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए आप काम में उनकी मदद मांग सकते हैं. इससे ना सिर्फ ऑफिस का प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, बल्कि काम के बीच में हंसी-मजाक करने से आपका रिश्ता भी बेहतर होने लगेगा. लेकिन, काम के दौरान पॉजिटिविटी बरकरार रखें और साथी कलीग की बुराई करने से बचें.

मोटिवेट करें

महिला कलीग को काम के प्रति मोटिवेट रखकर आप उनसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हैं. इससे फीमेल कलीग की ऑफिस परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगेगी. साथ ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे आप फीमेल कलीग के फेवरेट बन जाएंगे.

टी ब्रेक पर जाएं

ऑफिस के काम में लोगों को फीमेल कलीग से बात करने का मौका कम ही मिलता है. ऐसे में आप महिला कलीग को चाय या कॉफी का ऑफर दे सकते हैं मगर ध्यान रहे कि हर रोज महिला कलीग के साथ टी ब्रेक पर ना जाएं. इससे फीमेल कलीग के साथ आप बेस्ट प्रोफेशनल रिलेशन बना सकेंगे.

कस्तूरबा गांधी: बापू से लड़ीं-तर्क किए

नहीं माना मनमाना आदेश, पर हर फैसले में साथ रहीं, उजागर नहीं किए मतभेद

कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के सत्याग्रह समर्पण और त्याग में बराबर की सहभागी बनी। कुछ लोगों ने उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल माना तो कुछ ने सिर पर पल्लू लिए पति के पीछे-पीछे चलने वाली नितांत एक घरेलू महिला जिनकी अपनी कोई शख्सियत ही नहीं थी।

ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने। महान बने, देशवासियों के लिए भगवान बने। राष्ट्रपिता कहलाए, शांति और आजादी के दूत बने, लेकिन क्या यह सब उन्होंने अकेले अपने दम पर हासिल किया या फिर कोई मजबूत सहारा बन सालों साल खड़ा रहा?

इसके जवाब में एक नाम है- कस्तूरबा गांधी। यह वही नाम है, जो गांधी के सत्याग्रह, समर्पण और त्याग में बराबर का सहभागी बना। उनके हर कदम का साथी बना। तर्क-वितर्क किया, लेकिन हर फैसले को स्वीकार किया। कुछ लोगों ने उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना तो कुछ ने सिर पर पल्लू लिए पति के पीछे-पीछे चलने वाली नितांत एक घरेलू महिला, जिनकी अपनी कोई शख्सियत ही नहीं थी।

आज कस्तूरबा गांधी की जयंती है। इस अवसर पर पढ़िए कि 'बा' क्या थीं- एक घरेलू महिला या महिला सशक्तिकरण की मिसाल...

कस्तूरबा गांधी के जीवन पर किताब 'द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा' लिखने वाली लेखिका नीलिमा डालमिया आधार कहती हैं कि 'बा' बेहद पारंपरिक और पतिव्रता स्त्री थीं। शादी से लेकर आखिरी सांस तक गांधी के हर फैसले में साथ खड़ी रहीं। अच्छी पत्नी और मां बनने की कसौटी पर खरी उतरने में लगी रहीं।

घर संभाला, आश्रम संभाले। न सिर्फ अपने बच्चों, बल्कि आंदोलनकारियों पर भी ममता लुटाई। बा ने गांधी जी की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई को और मजबूत बनाया। महिलाओं को इसमें जोड़ा, जिससे हिंदुस्तान का घर-घर आजादी के इस आंदोलन से जुड़ा।

नीलिमा कहती हैं कि जब मैंने शोध किया तो हैरान रह गई। कस्तूरबा के बारे में सब सोचते हैं कि वह एक घरेलू महिला थीं, जो सिर्फ अपने पति का अनुसरण करती थी, जिनकी अपनी कोई शख्सियत ही नहीं थी, जबकि वे इसके बिल्कुल विपरीत थीं। वह बहुत आत्मनिर्भर और साहसी महिला थीं, जो गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलीं।

वक्त के सितम भी सहे...

वह आगे बताती हैं कि आज ही के दिन, यानी 11 अप्रैल, 1869 में उनका जन्म हुआ। कस्तूरबा एक बेहद धनी परिवार की बेटी थी। उनके पिता पोरबंदर के पूर्व मेयर गोकुलदास मकनजी कपाड़िया बेहद सम्मानित व्यापारी थे, जिनका विदेशों में कपड़े, अनाज और कॉटन का व्यापार था। समुद्र में उनके जहाज चलते थे। चार भाइयों की इकलौती बहन थीं। बहुत लाड-प्यार से पली-बढ़ीं, लेकिन गांधी परिवार में आने के बाद वक्त और गांधी दोनों के अत्याचार सहने पड़े।

जब 13 साल की उम्र में शादी कर मोहनदास की पत्नी बनी, तब कस्तूरबा मन से चंचल, लेकिन स्वभाव से समझदार व समर्पित पत्नी थीं। इसके इतर, गांधी बेहद डोमिनेटिंग एंड पजेसिव हजबैंड थे। वे कस्तूरबा को अपने मुताबिक चलाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए तरह-तरह की जुगत भिड़ाते। गांधी ने कस्तूरबा को आदेश दिया था कि वे बिना उनसे पूछे न कहीं जाएंगी और न कोई काम करेंगी, लेकिन कस्तूरबा ने गांधी के इस आदेश को नहीं माना। इससे चिढ़ कर गांधी कस्तूरबा के प्रति और कठोर हो गए।

गांधी के मनमाने आदेश को नहीं माना..

'सत्य के प्रयोग' में गांधी ने इस बात का जिक्र करते हुए लिखा है, 'मुझे एक पत्नी व्रत का पालन करना है तो पत्नी को एक पति व्रत का पालन करना चाहिए, यह सोचकर मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। पालन चाहिए से मैं पलवाना चाहिए के विचार पर चल पड़ा और मैंने पत्नी की निगरानी शुरू कर दी।

मैं सोचता... मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी कहां जाती है और क्यों? मेरी अनुमति के बिना वह कहीं नहीं जा सकती, लेकिन कस्तूरबा ऐसी कैद सहन करने वाली थी ही नहीं। जहां इच्छा होती, वहां मुझसे बिना पूछे जरूर जातीं। मैं जैसे-जैसे दबाव डालता, वैसे-वैसे वह अधिक आजादी से काम लेतीं और उतना ही मैं ज्यादा चिढ़ता।' हालांकि, बाद में गांधीजी ने कहा कि जैसे-जैसे मैं कस्तूरबा को जानता गया, वैसे-वैसे उनके प्रति प्रेम बढ़ता गया और उनका ज्यादा सम्मान करने लगा।

जब बा ने गांधी से कहा- तुम्हें थोड़ी शरम नहीं आती

साउथ अफ्रीका में गांधी जी स्वावलंबन को आगे बढ़ा

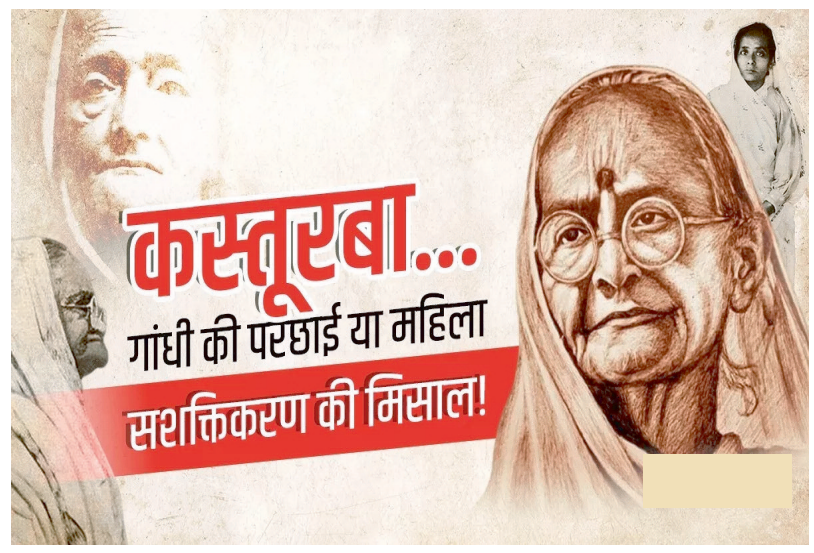

रहे थे। घर में नौकर नहीं थे। सभी को अपने काम स्वयं करने होते थे। उस वक्त अभी जैसे टॉयलेट नहीं होते थे, तब मैला खुद साफ कर फेंकना होता था। गांधी ने कस्तूरबा को अपने यहां आए मेहमान का मैला साफ करने को मजबूर किया तो वे गुस्से से फट पड़ी। कहा- बहुत हो चुका, अब वे नहीं करेंगी। इसके बाद दोनों के बीच बुरी तरह झगड़ा होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि गांधी कस्तूरबा को बांह पकड़ कर घर से बाहर निकालने लगे। इसके बाद बापू अपने किए शर्मिंदा हुए, लेकिन उन्होंने चेहरे पर सख्ती लाता हुए दरवाजा बंद कर दिया।

गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, "यह बिल्कुल वैसा ही था, जैसा मुझे एक अंग्रेज अधिकारी ने ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाला था। कस्तूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चिल्ला रहीं थी कि तुम्हें थोड़ी भी लाज शरम नहीं है? तुम अपने आप को इतना भूल गए? मैं कहां जाऊंगी? तुम सोचते हो कि तुम्हारी बीवी रहते हुए मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखने और तुम्हारी ठोकरें खाने के लिए हूं। भगवान के लिए अपना व्यवहार ठीक करो और गेट को बंद कर दो। इस तरह का तमाशा मत खड़ा करो।"

गांधी से लड़ीं, तर्क किए पर साथ नहीं छोड़ा

लेखिका नीलिमा डालमिया आगे बताती हैं कि कई जगहों पर कस्तूरबा और गांधी जी के विचार एक-दूसरे से नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में वह विरोध भी करतीं और अपने तर्क रखतीं। इसके बावजूद वह गांधी के साथ अडिग खड़ी रहतीं। गांधी जी ने कई ऐसे फैसले किए जो अमान्य हो सकते थे, लेकिन बा ने उन्हें माना और गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। मां और पत्नी के रूप में वह हमेशा समर्पित मनस्थिति में रहीं।

गांधी जी की बेटों के प्रति विचारों की असहमति का मुद्दा हो या फिर महिलाओं के साथ नाम जुड़ने का उन्होंने दोनों पर तक किए, लेकिन कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि उनके बीच मतभेद भी होते हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा को कभी बाहर नहीं आने दिया। हर फैसले में गांधी का साथ दिया।

अधिकार जताया, पर शक नहीं किया

आश्रम में गांधी महिलाओं के इर्द गिर्द घिरे रहते, लेकिन कस्तूरबा के मन में जरा भी संदेह नहीं हुआ। नीलिमा एक किस्सा सुनाती हैं, जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे, तब कैंप में वे बीमार पड़ गए। उस वक्त एक ब्रिटिश महिला मीरा बेन गांधी की विशेष अनुयायी हुआ करती थी। मीरा बेन ने कहा कि गांधी जी उनके साथ रहेंगे ताकि वे अच्छे से देखरेख कर सकें। उस वक्त 'बा' ने अपना अधिकार जताया। कहा- नहीं, वो मेरे साथ रहेंगे और मैं उनका ख्याल रखूंगी।

इसी तरह जब सरला देवी से गांधी का नाम जुड़ा तो उनके करीबी भी चिंतित हो उठे। सबको लगा कि गांधी ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़कर सरला से शादी तो नहीं कर लेंगे! गांधी के पोते तुषार ने एक इंटरव्यू में बताया कि बापू के करीबी लोग कस्तूरबा के पास पहुंचे और उनसे गांधी को समझाने की गुजारिश करने लगे, तब बा ने कहा, "तुम मेरे पति को पहचानते नहीं हो। मेरे पति को जो मुझमें नहीं मिल रहा है, वह दूसरों में ढूढ़ रहे हैं, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, वो कहीं नहीं जाएंगे।"

गांधी को बापू बनाने वाली सशक्त महिला

लेखिका बताती हैं कि एक बार की बात है, जब कस्तूरबा कलकत्ता (अब कोलकाता) में हरिलाल के दूसरे बेटे के जन्म के मौके पर गई थीं, तभी गांधी बीमार हो गए। जब कस्तूरबा को इसका पता चला तो वह लौट आईं। कस्तूरबा को देखकर गांधी जी बिलख पड़े और बोले कि तुम नहीं आती तो मैं मर जाता। दोनों के बीच प्रेम था। कस्तूरबा में पति के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी।

कस्तूरबा ने अपनी आखिरी सांस पुणे की आगाखान डिटेंसन कैंप में बापू की गोद में ली। जब बा का अंतिम संस्कार किया गया तो गांधी वहां तब बैठे रहे, तब तक चिता पूरी नहीं जल गई। जब चिता जल रही थी और गांधी शांत भाव से खड़े-खड़े देख रहे थे, तब किसी ने गांधी जी से कहा- कब तक खड़े रहेंगे थक जाएंगे। तब बापू ने जवाब दिया, '62 साल के साथी को क्या इस तरह छोड़ सकता हूं, यह अंतिम विदाई है। इसके लिए तो बा भी मुझे माफ नहीं करेगी।

गांधी के जीवन में छोड़ गई सूनापन

गांधी ने लिखा, 'बा को हमेशा ये अहसास रहा कि अगर वह चली जाएंगी तो मैं टूट जाउंगा। अगर बा का साथ न होता तो मैं इतना ऊंचा उठ ही नहीं सकता था। यह बा ही थीं, जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। नहीं तो भगवान जाने क्या ही होता? मेरी पत्नी मेरे अंतः को जिस प्रकार हिलाती थी, उस प्रकार दुनिया की कोई स्त्री नहीं हिला सकती। वह मेरे जीवन का अविभाज्य अंग थीं, उनके जाने से जो सूनापन पैदा हो गया है, वह कभी भर नहीं सकता।'

वाराणसी से मिशन साइबर शुरू करेंगी कामाक्षी, अलग-अलग शहरों में 20 लाख लोगों को करेंगी जागरूक

गाजियाबाद से वह 22 फरवरी को वाराणसी के लिए निकलेंगी जहां वह अपने साइबर मिशन की विधिवत शुरूआत करेंगी। विभिन्न राज्यों के अलग-अलग शहरों में वह स्कूल कालेज यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसायटी के अलावा सेमिनार आदि में लोगों के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाएंगी। उनका लक्ष्य वाराणसी से शुरुआत कर देश के विभिन्न राज्यों के अलग-अलग शहरों में 20 लाख लोगों को जागरूक करने का है।

गाजियाबाद। साइबर अपराध के चंगुल में लगातार फंस रहे लोगों को बचाने के लिए साइबर गर्ल कामाक्षी शर्मा 22 फरवरी से मिशन साइबर आरंभ करेंगी। उनका लक्ष्य वाराणसी से शुरुआत कर देश के विभिन्न राज्यों के अलग-अलग शहरों में 20 लाख लोगों को जागरूक करने का है।

वह वर्ष 2018-19 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक करीब 50 हजार से अधिक पुलिस अफसर व कर्मियों को 35 दिन के अभियान के तहत साइबर अपराध से बचाव और अपराधियों को पकड़ने का प्रशिक्षण दे चुकी हैं।

गाजियाबाद से वह 22 फरवरी को वाराणसी के लिए निकलेंगी, जहां वह अपने साइबर मिशन की विधिवत शुरूआत करेंगी। विभिन्न राज्यों के अलग-अलग शहरों में वह स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी, हाउसिंग सोसायटी के अलावा सेमिनार आदि में लोगों के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाएंगी।

लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करना लक्ष्य

साइबर अपराध के प्रति लोगों को लगातार जागरूक करने की मुहिम चलाने और मौजूदा दौर में इस महत्वपूर्ण मिशन को शुरू करने वाली कामाक्षी शर्मा को दुनिया भर में अलग पहचान मिली है।

कामाक्षी बताती हैं कि उनका लक्ष्य को देश भर के लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक कर हर पल हो रही ठगी और विभिन्न प्रकार के अपराधों से सचेत कर जागरूक करना है। इसके प्रति जागरूक हो चुके लोगों से भी उन्होंने मिशन साइबर में जुड़ने की अपील करते हुए कहा है कि वह दूसरे लोगों को भी इसके प्रति अपने इंटरनेट प्लेटफार्म से जागरूक करें।

कामाक्षी की बायोपिक दिखेगी सिल्वर स्क्रीन पर

साइबर मिशन में लाखों लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमीनार में जागरूक और विभिन्न राज्यों में पुलिस के साथ मिलकर सैंकड़ों साइबर अपराध पर काम कर चुकीं कामाक्षी की जीवनी और उपलब्धियों पर बायोपिक तैयार हो रही है।

उन्हें इस फिल्म में डिजिटल खतरों के खिलाफ लड़ाई में आशा की किरण के रूप में दिखाया जाएगा। मुल्क, धाकड़, सनम तेरी कसम, और शादी में जरूर आना फिल्म बनाने वाले सोहम राकस्टार एंटरटेनमेंट उनकी बायोपिक को सिल्वर स्क्रीन पर लाने की तैयारी कर रही है, जिसकी कास्टिंग हो चुकी है और जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देगी।

कुछ प्रमुख उपलब्धियां

2019 - वर्ल्ड फर्स्ट साइबर मिशन

2020 - इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड में दर्ज

2020 - एशिया बुक आफ रिकॉर्ड में दर्ज

2021- वर्ल्ड बुक आफ रिकॉर्ड में दर्ज

2022- जीवनी पर आधारित बायोपिक अपकमिंग

2022 - ग्रेट इंडिया पार्लियामेट अवॉर्ड

2023 - यूनाइटेड किंगडम एजेंसी में इंटरनेशनल साइबर वेल्यू स्पीकर के लिए चयन

2023 - गाजियाबाद गौरव सम्मान

2023 - फिल्म कलाकर नेहा धूपिया द्वारा ड्रीम्ज आइकोनिक अवॉर्ड

नोट : पिछले चार वर्षों में 60 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं।

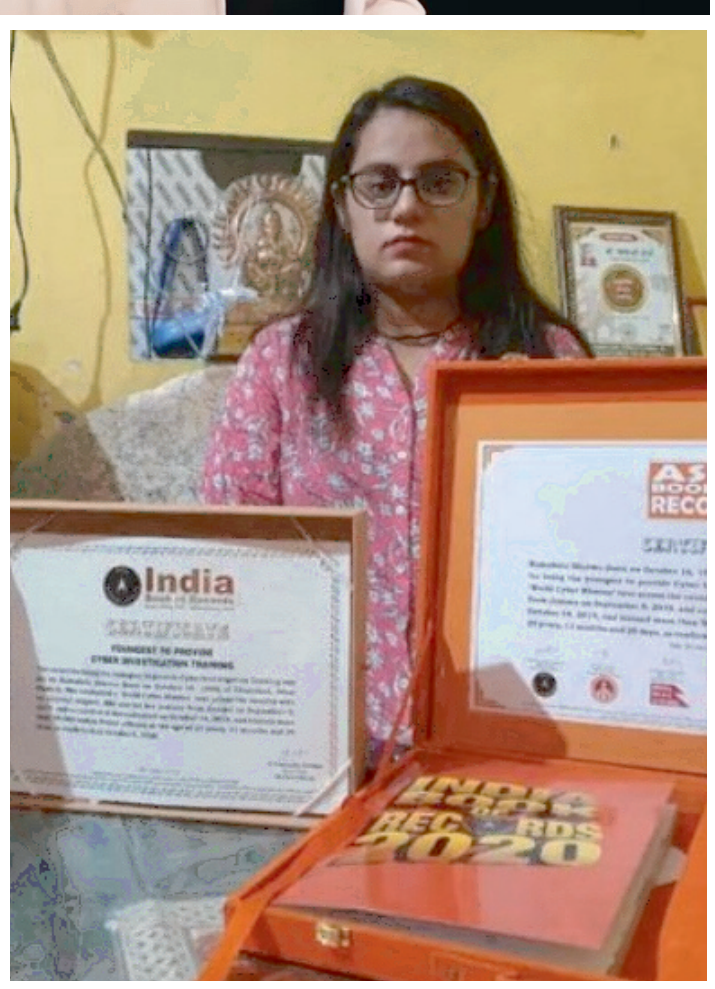

50 के बाद भी रहना है हेल्दी, 4 विटामिन्स को करें डाइट में शामिल, कम दिखने लगेगी उम्र, हमेशा रहेंगी फिट

पचास की उम्र के बाद महिलाओं में कमजोरी आने लगती है. ऐसे में महिलाएं अपनी बढ़ती उम्र को कम दिखाने की पूरी कोशिश करती हैं. वहीं, तमाम नुस्खे आजमाने के बाद भी महिलाएं अपनी ऐज को छुपाने में नाकाम हो जाती हैं. अगर आप 50 की हो रही हैं तो कुछ जरूरी विटामिन्स को डाइट (Diet tips) में एड करके आप उम्र के असर को आसानी से हाइड कर सकती हैं.

50 प्लस वुमेंस में विटामिन की कमी होना काफी आम बात है. ऐसे में विटामिन रिच डाइट को अवॉयड करने से ना सिर्फ महिलाएं फिजिकली वीक महसूस करने लगती हैं, बल्कि आपकी उम्र भी ज्यादा दिखती है. मेडिकलन्यूज़टुडे के मुताबिक, हम आपको बताते हैं 5 एसेंशियल विटामिन सप्लीमेंट्स के नाम, जिनका सेवन करके आप 50 के बाद भी खुद को यंग रख सकती हैं.

विटामिन बी 12

विटामिन बी 12 को एनर्जी का बेस्ट सोर्स माना जाता है. मगर बढ़ती उम्र के साथ शरीर में विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिलने लगती है. ऐसे में दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, चिकन, फिश, अंडा, मीट और खमीर जैसी चीजों को डाइट में शामिल करके आप विटामिन बी 12 की कमी पूरी कर सकती हैं.

कैल्शियम

कैल्शियम रिच डाइट हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार होती है. साथ ही कैल्शियम से भरपूर चीजें खाने से महिलाओं में फ्रैक्चर होने की संभावना कम रहती है. ऐसे में कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स, बीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, मछली, बीन्स, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियों, सोयाबीन और टोफू का सेवन कर सकती हैं.

विटामिन डी

50 से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं के लिए विटामिन डी का सेवन भी जरूरी होता है. विटामिन डी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और थकान को दूर रखने में सहायक होता है. वहीं डेयरी प्रोडक्ट, अंडा और फिश को विटामिन डी का बेहतर स्रोत माना जाता है. इसके अलावा बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए आप कुछ देर धूप में भी बैठ सकती हैं.

विटामिन बी 6

50 के बाद शरीर में विटामिन बी 6 की कमी होने लगती है. ऐसे में फिट और हेल्दी रहने के लिए विटामिन बी 6 से भरपूर आहार लेना जरूरी हो जाता है. वहीं गाजर, पालक, केला, दूध, चिकन और कलोंजी को विटामिन बी 6 का बेस्ट सोर्स माना जाता है.

लोकपाल की कार्यवाही मामले में शिबू सोरेन ने दायर की अपील, बीजेपी सांसद की शिकायत पर हो रही सुनवाई

परिवहन विशेष न्यूज

निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर लोकपाल द्वारा शुरू की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो संरक्षक शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की। सोमवार को मामला जब न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ के समक्ष आया तो अदालत ने मामले को 20 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

नई दिल्ली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर लोकपाल द्वारा शुरू की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो संरक्षक शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की है। सोमवार को मामला जब न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ के समक्ष आया तो अदालत ने मामले को 20 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

सुनवाई के दौरान शिबू सोरेन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला मंगलवार को ही लोकपाल में भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस पर पीठ ने कहा कि मामले को पूरक सूची में शामिल किया गया है और सुबह ही इस पर सुनवाई की जाएगी। लोकपाल में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर सुनवाई कर रहा है।

निशिकांत ने सोरेन पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया गया है। 22 जनवरी को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने लोकपाल कार्यवाही और शिकायत के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया था।

सोरेन की याचिका पहले से दायर

एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि लोकपाल की कार्यवाही को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका समय से पहले दायर की गई थी। अदालत ने कहा था कि अभी लोकपाल को यह देखना बाकी है कि जांच में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है या नहीं।

अगस्त 2020 में की गई शिकायत में सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके भारी संपत्ति और संपत्ति अर्जित की और घोर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं।

लोकपाल ने तब सीबीआई को सोरेन के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला मौजूद है या नहीं।

इस दिन ट्रैक्टर से दिल्ली जाएंगे किसान, राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा एलान; कहा- एमएसपी गारंटी कानून के बिना...

परिवहन विशेष न्यूज

किसानों के दिल्ली कूच के एलान के बीच राकेश टिकैत ने बड़ा एलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार एमएसपी गारंटी कानून बनने तक किसान अपनी मांग के साथ अड़ा रहेगा। हम किसानों को समर्थन करते हैं। भाकियू कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश उत्तराखंड़ हरियाणा आदि राज्यों के जिला मुख्यालयों पर 21 फरवरी को ट्रैक्टरों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद किसान टैक्टरों के साथ दिल्ली...

गाजियाबाद। भिकनपुर दुहाई में भाकियू महिला प्रकोष्ठ की महिला किसान मजदूर महापंचायत मे संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। एमएसपी गारंटी कानून बनने तक किसान अपनी मांग के साथ अड़ा रहेगा।

सरकार ने बर्बरता की पार की हद- टिकैत

उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों पर बर्बरता की हद पार रखी है। हम अभी दिल्ली नहीं जा रहे तो यूपी बॉर्डर का रास्ता जाम कर आमजन को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने जा रहे किसानों पर बर्बरता अंग्रेजी शासनकाल की याद दिलाता है।

इस दिन ट्रैक्टर से दिल्ली जाएंगे किसान

राकेश टिकैत ने कहा कि किसान भी इसी देश के नागरिक हैं, जिनके साथ मर्यादित व्यवहार किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का हक है। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को किसान ट्रैक्टरों के साथ एक दिन के लिए दिल्ली जाएंगे, लेकिन इससे पहले भाकियू कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश उत्तराखंड़, हरियाणा आदि राज्यों के जिला मुख्यालयों पर 21 फरवरी को ट्रैक्टरों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे।

केंद्र सरकार का MSP पर फार्मूला मंजूर नहीं

रास्ते से अवरोधक हटाए जाएं, ताकि आमजन को भी समस्या न हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसपी पर जो फार्मूला निकाला है, वह मंजूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा जो अनिश्चितकालीन होगा।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा ट्रैक्टर खेतों में भी चलेगा और दिल्ली की सड़कों पर भी दौड़ेगा। इस मौके पर महिला राष्ट्रीय सचिव केतकी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बबली त्यागी, महिला जिलाध्यक्ष ममता चौधरी, वंदना चौधरी के अलावा भाकियू पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

केजरीवाल ईडी के समन पर छठी बार फिर गैर हाजिर

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी के छठे समन को भी सोमवार को एक बार फिर गैरहाजिर रहे। उनके द्वारा ईडी के लगातार पेशी के नाफरमानी पर मामला गंभीर माना जा रहा है।

कोर्ट में पेशी की अगली तारीख 16 मार्च है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के पहले 3 समन पर ईडी दफ्तर में पेश न होने के बाद उन पर आईपीसी की धारा 174 (किसी आदेश के अनुपालन में गैरहाजिर का मामला बनता था। इसे लेकर ही ईडी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी।जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। ईडी सूत्रो की माने तो कोर्ट में मामला ईडी द्वारा जारी समन की वैधता को लेकर नहीं है, बल्कि 3 समन की जान जानबूझकर अवहेलना करना है। जो कि एक अपराध है।

अदालत ने केंद्रीय ऐजेंसी द्वारा दायर शिकायत के संबंध में केजरीवाल को शनिवार को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से राहत देती थी। फिलहाल दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू हो गया है।और मार्च के पहले हफ्ते तक चलेगा। केजरीवाल के वकील ने कहा है कि वह 16 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश होगे।

सांसद प्रिंस राज को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, दुष्कर्म मामले में अग्रिम जमानत रखी बरकरार

दुष्कर्म के आरोप में फंसे स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के भतीजे व लोक जनशक्ति पार्टी सांसद प्रिंस राज को निचली अदालत से दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि राज को ट्रायल कोर्ट द्वारा 2021 में मामले से जुड़े तथ्यों व सामग्री पर विचार करने के बाद राहत दी गई थी।

नई दिल्ली। दुष्कर्म के आरोप में फंसे स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के भतीजे व लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के सांसद प्रिंस राज को निचली अदालत से दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि राज को ट्रायल कोर्ट द्वारा 2021 में मामले से जुड़े तथ्यों व सामग्री पर विचार करने के बाद राहत दी गई थी।

शिक्षा हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है इस शिक्षा प्राप्त करें:वक्ता

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन, सेलिंग क्लब रोड बटला हाउस, जामिया नगर, दिल्ली में जलसा ए दस्तार बंदी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में तंज़ीम उलेमा ए हक के अध्यक्ष मौलाना इजाज उर्फी कासमी ने भाग लिया। अध्यक्षता प्रोफेसर मौलाना अब्दुल कादिर कासमी ने की। मौलाना मुफ्ती मुहम्मद साकिब कमर न दवी ने निजामत की रस्म अदा की। इस मौके पर हाफिज मुहम्मद गुफ़रान , हाफिज मुहम्मद गालिब और हाफिज मुहम्मद संजर को दस्तार दी गई। शायर ए इस्लाम हाफिज अरशद, मोहम्मद मंजर और कारी यूसुफ ने नात शरीफ पेश की।

हजरत मौलाना इश्तियाक़ कासमी चतुर्वेदी, पूर्णिया बिहार ,मौलाना शाकिर साहब कासमी, अल-उमर मस्जिद के इमाम और खतीब, हजरत मौलाना मुफ्ती शखावत कमर हुसैनी (इमाम व खतीब), मौलाना शाह कमर-उज़ -जमान इलाहाबादी मुहम्मदी मस्जिद शाहीन बाग, मौलाना गुलाम रब्बानी कासमी बिजनौर यूपी एवं मौलाना मुफ्ती मुबश्शिर अहमद कासमी ने संबोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि वे माता-पिता धन्य हैं जिनके बच्चों ने पवित्र कुरान को अपने सीने में सुरक्षित रखा है क्योंकि कुरान अल्लाह का सबसे अच्छा कलाम है जिसमें परिवर्तन के लिए कोई जगह नहीं है और कुरान की रक्षा की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को कुरान और दीनी शिक्षा दिलाएं। उन्होंने कहा कि उलमाओं की कद्र करें क्योंकि उलमाओं का महत्व मुसल्लम है, वे जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनें और जितना उस पर अमल करने का प्रयास करें क्योंकि उलमा लोगों के मार्गदर्शन को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानते हैं। और मदरसों से जुड़े हैं वह बधाई के पात्र हैं।

अंत में मदरसा इइस्लाहुल -मुस्लिमीन के अध्यक्ष हाफिज और कारी मोहम्मद रुस्तम ने अतिथियों, वक्ताओं और दर्शकों का शुक्रिया अदा किया।

'मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ग्राउंड पर बम लगा दिया है', रात को युवक के कॉल से मचा हड़कंप

दिल्ली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसने पब्लिसिटी (फेमस होने के लिए) पाने के दिल्ली एयरपोर्ट पर बम लगाने की धमकी दी थी। आरोपी की पहचान पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी निवासी कुशाग्र अग्रवाल के रूप में हुई है। आरोपी ने 18 फरवरी की रात कॉल कर कहा था कि मैंने एयरपोर्ट ग्राउंड में बम लगा दिया है।

नई दिल्ली। 18 फरवरी को गुरुग्राम स्थित डायल (DIAL) के कॉल सेंटर में कॉल करके एक युवक ने कहा कि मैंने एयरपोर्ट ग्राउंड में बम लगा दिया है। कॉल सेंटर से तत्काल यह सूचना आईजीआई थाना पुलिस को मिली। जब पुलिस ने इस सूचना के आधार पर छानबीन शुरू की तब यह सूचना फर्जी पाई गई। बाद में पुलिस ने छानबीन के दौरान झूठी सूचना देने वाले युवक को दबोच लिया। आरोपित युवक का नाम कुशाग्र अग्रवाल है। पुलिस ने जब आरोपित से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने ऐसा केवल पब्लिसिटी पाने के लिए किया था। आईजीआई जिला पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि जब बम से जुड़ी सूचना मिलने के बाद हाई अलर्ट व फुल इमरजेंसी घोषित किया गया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विरेंद्र राणा की अगुवाई में टीम का गठन किया गया। पुलिस ने फौरन कॉलर के नंबर पर कॉल किया, लेकिन आरोपित काल रिसीव नहीं कर रहा था।

बार-बार कोशिश की गई लेकिन अंत में मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी छानबीन शुरू की। पता चला कि जिस नंबर से कॉल किया गया है वह कुशाग्र अग्रवाल के नाम से रजिस्टर्ड है।

'दिल्ली का सबसे बड़ा धमाका होगा', HC को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला कौन? पुलिस ने की पहचान

परिवहन विशेष न्यूज

बीते बुधवार को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को बलवंत देसाई के नाम से ईमेल आया था जिसमें उसने कहा था कि 15 फरवरी को हाई कोर्ट में जोरदार धमाका होगा। हालांकि धमकी भरा मेल करने के बाद आरोपित ने अलग-अलग तिथियों में दो और मेल किया है। अब स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए धमकी भरे मेल भेजने वाले की पहचान कर ली है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपित की पहचान कर ली है। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल सेल की टीम को कर्नाटक भेजी गई है, लेकिन अभी सेल उसे नहीं पकड़ पाई है। बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल करने के बाद आरोपित ने अलग-अलग तारीखों में दो और मेल किया है।

ईमेल भेजकर पुलिस से मांगी माफी

एक मेल में उसने अग्निवीर योजना को लेकर गुस्सा जताया और दूसरे में कहा है कि उससे गलती हो गई। दिल्ली पुलिस उसे माफी दे दे। हाई कोर्ट को अब तक तीन मेल कर अलग-अलग बातें करने को लेकर दिल्ली पुलिस का मानना है कि आरोपित मानसिक रोगी भी हो सकता है। गत दिनों ईमेल से धमकी मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट परिसर के साथ ही दिल्ली की सभी निचली अदालतों की सुरक्षा बढ़ा दी थी।

धमकी भरे ईमेल भेजने वाले की हुई पहचान

विशेष आयुक्त स्पेशल सेल आरएस उपाध्याय का कहना है कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपित ने अपने सही ईमेल के जरिये मेल भेज धमकी दी है, जिससे उसकी पहचान कर ली गई है। बता दें बीते बुधवार को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को बलवंत देसाई के नाम से ईमेल आया था, जिसमें उसने कहा था कि 15 फरवरी को हाई कोर्ट में जोरदार धमाका होगा।

धमकी मिलने पर बढ़ाई गई थी सुरक्षा

कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। यह दिल्ली का सबसे बड़ा धमाका होगा। आप यथासंभव अपनी सुरक्षा बढ़ाएं और सभी मंत्रियों को हाई कोर्ट में बुलाएं। हर किसी को उड़ा दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने धमकी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने उसी दिन परिसर समेत उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी थी।

सुरक्षा इसलिए कड़ी कर दी गई क्योंकि इससे पहले दो बार हाई कोर्ट के गेट पर धमाका हो चुका है। रजिस्ट्रार ने सभी जिला अदालतों के प्रधान न्यायाधीशों को भी तुरंत सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए थे। 15 फरवरी को हाई कोर्ट में सुरक्षा ड्रिल भी कराई की गई थी।

किसान आंदोलन के चलते दिल्ली से जम्मू सराफा बाजार तक की चमक फीकी, करोड़ों रुपये कारोबार प्रभावित

किसानों के दिल्ली कूच के एलान से कारोबार पर खासा असर पड़ रहा है। दिल्ली के ज्वैलरी बाजार से जुड़े लोगों के अनुसार किसानों के दिल्ली कूच करने से हफ्तेभर से उनका कारोबार कम से कम 150 करोड़ रुपये तक प्रतिदिन प्रभावित हो रहा है क्योंकि उनके यहां पंजाब जम्मू-कश्मीर हिमाचल समेत अन्य राज्यों से आने वाले खरीदारों की संख्या काफी कम हुई है।

नई दिल्ली। किसानों के कूच ने दिल्ली से लेकर जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के ज्वैलर्स बाजार की चमक को फीकी किया है। बड़ा असर ज्वैलरी के हब राष्ट्रीय राजधानी के कूचा महाजनी, दरीबा कलां व करोलबाग जैसे बाजारों पर पड़ा है, जिसका कारोबार 30 से 40 प्रतिशत तक प्रभावित है। दिल्ली में करीब 10 हजार ज्वैलरी प्रतिष्ठान है।

दिल्ली में कारोबार पर खासा असर

इसी तरह सैकड़ों ज्वैलरी निर्माण के यूनिट्स हैं, जहां थोक व खुदरा में प्रतिदिन करीब 500 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। दिल्ली के ज्वैलरी बाजार से जुड़े लोगों के अनुसार किसानों के दिल्ली कूच करने से हफ्तेभर से उनका कारोबार कम से कम 150 करोड़ रुपये तक प्रतिदिन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उनके यहां पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल समेत अन्य राज्यों से आने वाले खरीदारों की संख्या काफी कम हुई है, क्योंकि इन राज्यों के आने वाले खरीदारों में 90 प्रतिशत ऐसे हैं जो खुद अपने वाहनों से दिल्ली खरीदारी के लिए आते हैं।

वैसे, यह स्थिति तब है जब दिल्ली समेत प्रभावित राज्यों में हजारों शादियां प्रतिदिन हो रही है, जिसमें ज्वैलरी की मांग सर्वाधिक निकलती है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, पंजाब के अध्यक्ष रवि कुमार हाठी के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित पंजाब के ज्वैलर्स हुए हैं। उनका दिल्ली से कनेक्शन पूरी तरह से कटा हुआ है।

इसी तरह, सराफा एसोसिएशन, जम्मू के अध्यक्ष रमन सूरी ने कहा कि दिल्ली ज्वैलरी के मामले में हब है। वहां हर प्रकार की ज्वैलरी मिल जाती है। इसलिए जम्मू-कश्मीर के ज्वैलर्स का प्रमुख ठिकाना दिल्ली है, जो चुनिंदा बड़े ज्वैलर्स हैं, वह तो हवाई कुरियर के माध्यम से ज्वैलरी मंगवा ले रहे हैं, लेकिन 90 प्रतिशत छोटे ज्वैलर्स सड़क मार्ग बाधित होने से प्रभावित हैं। इसलिए आस-पास के ज्वैलरी बाजारों से किसी प्रकार ऑर्डर पूरी किए जा रहे हैं।

किसान आंदोलन से दिल्ली जाना कम

हरियाणा के ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार लांबा के अनुसार अधिकतर ज्वैलर्स खुद जाकर दिल्ली से खरीदारी करते हैं, ऐसे में जब रास्ते प्रभावित हैं तो ट्रेन के माध्यम से ज्वैलरी मंगाई जा रही है, लेकिन वह अनिवार्य स्थिति में ही है। इसलिए, रोहतक, अंबाला जैसे आसपास के बाजारों से ज्वैलरी उठाई जा रही है, लेकिन वह थोड़ी महंगी तथा वैरायटी भी सीमित है। हिमाचल के अतुल तंगडी के अनुसार, हिमाचल के ज्वैलर्स वैकल्पिक मार्ग यमुना नगर होते हुए दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे उनका यात्रा समय काफी बढ़ गया है। इसलिए दिल्ली जाना कम हुआ है।

द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, कूचा महाजनी के चेयरमैन योगेश सिंगल के अनुसार, दूसरे राज्यों के ज्वैलर्स ही नहीं दिल्ली के बाजारों में वहां के खरीदारों की भी बड़ी संख्या होती है, जो खुद के लिए ज्वैलरी लेने आते हैं। उनकी संख्या भी किसानों के कूच ने प्रभावित की है।

राजनगर एक्सटेंशन में बनेगा वर्किंग स्टेशन, घंटे के हिसाब से लिया जाएगा शुल्क; मिलेंगी कई सुविधाएं

परिवहन विशेष न्यूज

आपके पास नौकरी है लेकिन कार्य करने के लिए जगह नहीं है तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वर्किंग स्टेशन के अंदर ही मीटिंग हॉल पार्टी हॉल और ठहरने के लिए कमरे भी बनाए जाएंगे इससे लोगों को गाजियाबाद में ठहरने में परेशानी का सामना न करना पड़े। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलेगा तो दूसरी तरफ नगर निगम की आय भी बढ़ेगी।

गाजियाबाद। यदि आपके पास नौकरी है, लेकिन कार्य करने के लिए जगह नहीं है तो इस समस्या का समाधान डेढ़ साल में हो जाएगा। नगर निगम द्वारा राजनगर एक्सटेंशन में बन रहे सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के ऊपर वर्किंग स्टेशन बनाया जाएगा, जहां पर प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क लेकर लोगों का कार्य करने के लिए जगह दी जाएगी।

बढ़ेंगी नगर निगम की आय

वर्किंग स्टेशन के अंदर ही मीटिंग हॉल, पार्टी हॉल और ठहरने के लिए कमरे भी बनाए जाएंगे, जिससे कि दूर से आने वाले लोगों को गाजियाबाद में ठहरने में परेशानी का सामना न करना पड़े। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलेगा तो दूसरी तरफ नगर निगम की आय भी बढ़ेगी।

दरअसल, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा परिवार से अलग रह रहे लोगों को अकेलेपन का एहसास न हो, इसके लिए राजनगर एक्सटेंशन में सीनियर सिटीजन केयर सेंटर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को शासन से अनुमति मिली चुकी है, निर्माण कार्य जल निगम की सीएंडडीएस विंग द्वारा किया जा रहा है।

सीनियर सिटीजन केयर सेंटर भी बनेगा

सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के अंदर बुजुर्गों के लिए डिस्पेंशरी, योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, कैंटीन, जिम्नेजियम के साथ ही मनोरंजन के लिए इंडोर गेम्स और टीवी की व्यवस्था के साथ ही लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। दो करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सीनियर सिटीजन केयर सेंटर का निर्माण कार्य तीन दिन पहले शुरू कर दिया गया है।

इसे पूरा होने में एक साल का वक्त लगेगा। इसके बाद सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के ऊपर वर्किंग स्टेशन बनाने का कार्य शुरू कराया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत तीन करोड़ 84 लाख रुपये है। यह कार्य भी वर्ष 2025 में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

अतीत और भविष्य की दिखेगी झलक

सीनियर सिटीजन केयर सेंटर और वर्किंग स्टेशन का निर्माण कार्य एक ही बिल्डिंग में होने से यहां आने वाले बुजुर्गों को एक तरफ अपने अतीत की झलक वर्किंग स्टेशन में कार्य कर रहे लोगों में दिखाई देगी तो दूसरी तरफ वर्किंग स्टेशन के अंदर कार्य कर रहे लोग सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के अंदर रह रहे बुजुर्गों में अपने भविष्य की झलक देख सकेंगे।

सीनियर सिटीजन केयर सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, इसी बिल्डिंग में ही वर्किंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जा चुका है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट का कार्य शुरू किया जाएगा। इससे बुजुर्गों और नौकरीपेशा लोगों को मदद मिलेगी।

- एनके चौधरी, मुख्य अभियंता, निर्माण विभाग, नगर निगम।

दक्षिण हरियाणा की सीटों पर कमल खिलाने के लिए मंथन, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिली ये जिम्मेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

दक्षिण हरियाणा की तीन सीटों पर कमल खिलाने के लिए भाजपा ने दो घंटे तक मंथन किया। दिल्ली में हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा को 370 सीटें जिताने और एनडीए को 400 पार कराने का लक्ष्य दिया है। क्लस्टर प्रभारी ग्रोवर ने पदाधिकारियों को अपने-अपने बूथों को और अधिक मजबूत करने के लक्ष्य के साथ-साथ बूथों पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य भी दिया।

गुरुग्राम। दक्षिण हरियाणा के तीनों लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव, फरीदाबाद एवं महेंद्रगढ़-भिवानी में कमल खिलाने के लिए सोमवार को भाजपा ने प्रदेश कार्यालय गुरुकमल में मंथन किया। लगभग दो घंटे तक चली मंथन की अध्यक्षता क्लस्टर प्रभारी मनीष ग्रोवर ने की।

28 फरवरी को आयोजित होंगे सम्मेलन

28 फरवरी को तीनों क्षेत्र के भिवानी, नूंह एवं फरीदाबाद जिले में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। तीनों सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शरीक होंगे। मंथन के दौरान क्लस्टर प्रभारी मनीष ग्रोवर ने सबसे पहले तीनों लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर चल रही तैयारी के बारे में विधानसभा स्तर पर पदाधिकारियों से फीडबैक लिया।

बैठक में शामिल गुड़गांव, फरीदाबाद और भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और चुनाव प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी उपलब्ध कराई। जानकारी हासिल करने के बाद मनीष ग्रोवर ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 28 फरवरी को हरियाणा प्रवास पर रहेंगे। भिवानी में लोकसभा की बूथ समितियों की एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।

गुड़गांव लोकसभा की चुनाव संचालन और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक नूंह में होगी। फरीदाबाद में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन होगा। ये तीनों कार्यक्रम 28 फरवरी को ही होंगे। तीनों कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। दिल्ली में हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा को 370 सीटें जिताने और एनडीए को 400 पार कराने का लक्ष्य दिया है। राष्ट्रीय अधिवेशन से कार्यकर्ताओं को नई उर्जा और नई ताकत मिलेगी।

हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य

ग्रोवर ने उपस्थित पदाधिकारियों को अपने-अपने बूथों को और अधिक मजबूत करने के लक्ष्य के साथ-साथ बूथों पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य भी दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोदी-मनोहर सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने का आग्रह भी किया। कार्यकर्ता हर बूथ पर घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करें। गुड़गांव लोकसभा प्रभारी अजय गौड़, गुड़गांव लोकसभा संयोजक मनीष मित्तल, प्रदेश सरकार में मंत्री डॉ. बनवारी लाल, फरीदाबाद लोकसभा संयोजक विधायक दीपक मंगला, महेंद्रगढ़-भिवानी लोकसभा प्रभारी शंकर धूप्पड़, लोकसभा संयोजक विधायक लक्ष्मण यादव ने भी विचार रखे।

बैठक में गुरुग्राम जिलाध्यक्ष कमल यादव, रेवाड़ी जिलाध्यक्ष प्रीतम चैहान, नूंह जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल, फरीदाबाद जिलाध्यक्ष राज कुमार बोहरा, पलवल जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, महेंद्रगढ़ जिलाध्यक्ष दयाराम आदि शामिल हुए।

परीक्षार्थी और उसके स्थान पर परीक्षा देने वाला रंगे हाथ दबोचा, 5 लाख रुपये देने का किया था वादा

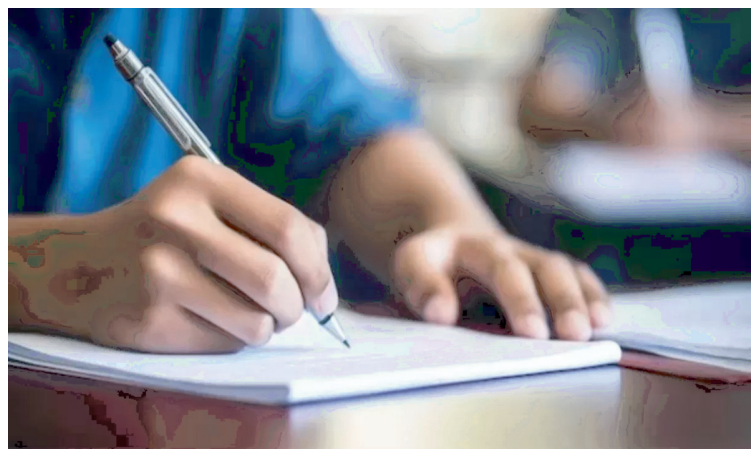

पुलिस ने सेक्टर-71 स्थित ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में बने परीक्षा केंद्र से आरोपित को पकड़ा। पूछताछ में हरीश ने पुलिस को बताया कि बादल को परीक्षा देने की आवाज में पांच लाख रुपये देने का वादा किया था। बादल ने हरीश को परीक्षा में शत प्रतिशत सफलता की गारंटी दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

नोएडा। कोतवाली फेज-तीन पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देते एक साल्वर को रविवार शाम दूसरी पाली में रंगे हाथ पकड़ लिया। जांच के बाद पुलिस ने असली परीक्षार्थी को भी गिरफ्तार कर लिया।

परीक्षार्थी की पहचान हरीश पाल निवासी उदयपुर थाना जहांगीरपुर बुलंदशहर के रूप में हुई है। हरीश की जगह उसका परिचित बादल चौधरी निवासी नेकपुर थाना जहांगीरपुर बुलंदशहर परीक्षा दे रहा था।

पुलिस ने सेक्टर-71 स्थित ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में बने परीक्षा केंद्र से आरोपित को पकड़ा। पूछताछ में हरीश ने पुलिस को बताया कि बादल को परीक्षा देने की आवाज में पांच लाख रुपये देने का वादा किया था। बादल ने हरीश को परीक्षा में शत प्रतिशत सफलता की गारंटी दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

पति की मौत से दुखी महिला ने फांसी लगाकर दी जान, अनाथ हो गए तीन बच्चे

पति की मौत से दुखी महिला ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में फांसी लगाकर जान दे दी। महिला के पति की तीन महीने पहले सड़क हादसे में मौत हुई थी। पुलिस के मुताबिक बाइपास निवासी 40 वर्षीय महिला बबीता का शव फंदे पर लटका हुआ मिला था। महिला के तीन बच्चे हैं। महिला के पति श्याम की तीन महीने पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी।

गाजियाबाद। पति की मौत से दुखी महिला ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में फांसी लगाकर जान दे दी। महिला के पति की तीन महीने पहले सड़क हादसे में मौत हुई थी। पुलिस के मुताबिक बाइपास निवासी 40 वर्षीय महिला बबीता का शव फंदे पर लटका हुआ मिला था।

महिला के तीन बच्चे हैं। महिला के पति श्याम की तीन महीने पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद से महिला तनाव में थी। पुलिस का कहना है कि महिला के तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा 24 वर्ष, उससे छोटा बेटा 22 वर्ष एवं 20 वर्ष की बेटी है।

करंट से महिला की मौत हुई

गाजियाबाद के नंदग्राम में आश्रम रोड पर एक दोने-पत्तल बनाने की फैक्ट्री में काम कर रही महिला की करंट लगने से मौत हो गई। महिला को करंट लगने पर यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस के मुताबिक आश्रम रोड पर 37 वर्षीय सीमा को शनिवार शाम को करंट लगा था। फैक्ट्री संचालक ने महिला को यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। स्वजन ने पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी है।

सॉल्वर ने सफलता की दी गारंटी, परीक्षार्थी के स्थान पर दी थी यूपी पुलिस की परीक्षा; दो गिरफ्तार

कोतवाली फेज-तीन पुलिस ने परीक्षार्थी के स्थान पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा (UP Police Recruitment Exam) दे रहे सॉल्वर और परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित पांच लाख रुपये के एवज में परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान सेक्टर-71 स्थित ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में बने केंद्र में आरोपित का फर्जीवाड़ा पकड़ में आया।

नोएडा। कोतवाली फेज-तीन पुलिस ने परीक्षार्थी के स्थान पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा (UP Police Recruitment Exam) दे रहे सॉल्वर और परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित पांच लाख रुपये के एवज में परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान सेक्टर-71 स्थित ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में बने केंद्र में आरोपित का फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में शामिल परीक्षार्थी के भाई को भी आरोपित बनाया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

रविवार को किया गिरफ्तार

डीसीपी सुनीति ने बताया कि जिले में बीते शनिवार और रविवार को दो-दो पालियों में पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित हुई। रविवार को दूसरी पाली में सेक्टर-71 स्थित केंद्र पर परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा एक सॉल्वर गिरफ्तार किया।

इस तरह पकड़ में फर्या फर्जीवाड़ा

आरोपित की पहचान जिला बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर के गांव नेकपुर के बादल चौधरी के रूप में हुई। आरोपित का फर्जीवाड़ा बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान पकड़ में आया। आरोपित के पास से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी प्रवेश पत्र, एक ओएमआर उत्तर पत्रक, एक प्रश्न पुस्तिका 12 वर्क, दो मोबाइल फोन, एक पासपोर्ट साइज फोटो व एक काला पैन बरामद हुआ।

राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए किसानों की भावनाएं भड़काई गयी हैं

स्वाधीन भारत में कई किसान आंदोलन हुए। बेशक हमारा देश अब औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का बड़ा हब बनता जा रहा है, लेकिन अब भी देश की बड़ी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है। एक आंकड़े के मुताबिक अब भी ग्रामीण आबादी का 54 फीसद हिस्सा सिर्फ खेती और किसानी पर ही निर्भर है।

उमेश चतुर्वेदी

खेती-किसानी की संस्कृति वाले अपने देश की विडंबना कहेंगे या फिर कुछ और...गुलाम भारत में बदहाल रही खेती-किसानी को लेकर आजाद भारत में भी क्रांतिकारी बदलाव नहीं आ पाया। राजनीति का खेल कहें या शासन व्यवस्था की नाकामी, आजाद भारत के सारे चुनावों में किसानों की स्थिति मुद्दा रही। वामपंथी धारा की राजनीति हो या राष्ट्रवादी धारा की, समाजवादी हों या मध्यमार्गी, हर राजनीतिक दल, सभी चुनावों में किसान, मजदूर और गरीब को ही मुद्दा बनाता रहा। लेकिन आजादी के पचहत्तर साल बाद भी संपूर्ण भारत भूमि को वैसी चमक हासिल नहीं हो पाई, जैसी औद्योगिक क्रांति के बाद के महज डेढ़ सौ सालों में ही यूरोप ने हासिल कर लिया। बेशक भारत आज दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर वह तेजी से अग्रसर भी है। लेकिन इस आर्थिक विकास का आनुपातिक हिस्सा गरीबों, मजदूरों और किसानों को नहीं मिल पाया है। मौजूदा किसान आंदोलन को लेकर अगर देश के एक बड़े वर्ग में सहानुभूति है तो इसकी एक बड़ी वजह हमारी व्यवस्था की नाकामी से उपजा असंतुलन ही है। किसानों को लेकर बनी सोच का ही नतीजा है कि दो साल पहले हुए किसान आंदोलन की हिंसा और हठधर्मिता के बावजूद देश का एक बड़ा हिस्सा उनके प्रति हमदर्दी रखता रहा है।

स्वाधीन भारत में कई किसान आंदोलन हुए। बेशक हमारा देश अब औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का बड़ा हब बनता जा रहा है, लेकिन अब भी देश की बड़ी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है। एक आंकड़े के मुताबिक अब भी ग्रामीण आबादी का 54 फीसद हिस्सा सिर्फ खेती और किसानी पर ही निर्भर है। अपना देश विशाल है और स्थानीय स्तर पर लोगों की अपनी-अपनी समस्याएं भी रहती ही हैं। स्वाधीन भारत ने जिस ब्यूरोक्रेसी को अपनाया है, कई बार उसकी जड़ सोच की वजह से भी स्थानीय स्तर पर समस्याएं उपजती ही रहती हैं। उसकी वजह से स्थानीय स्तर पर हर समय देश के किसी ना किसी हिस्से में किसान आंदोलन होते ही रहते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में बड़े किसान आंदोलन अगर हुए हैं, उनमें प्रमुख रूप से तीन-चार के ही नाम गिनाए जा सकते हैं। पिछली सदी के अस्सी के दशक में भारतीय किसान यूनियन नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुआई में हुआ आंदोलन इनमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय रहा है। शायद यह पहला मौका था, जब किसानों ने दिल्ली के वोट क्लब को घेर लिया था। जब नरसिंह राव ने उदारीकरण की नीतियां स्वीकार कीं, भारत जब विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बना, तब शेतकारी संगठन जैसे किसान संगठनों की अगुआई में खेती में विदेशी हस्तक्षेप और भारतीयता की परंपरा को खत्म करने की आशंकाओं के खिलाफ पिछली सदी के आखिरी दशक में लंबा आंदोलन चला।

हरियाणा में बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर हुए आंदोलन को भी इस सूची में जोड़ सकते हैं। लेकिन अतीत के ये आंदोलन कभी हिंसक नहीं रहे। अगर किंचित हिंसा हुई भी तो उसके निशाने पर सार्वजनिक स्थल आदि ही रहे। लेकिन पिछले दो साल से हो रहे किसान आंदोलन को लेकर ऐसा नहीं कहा जा सकता। दो साल पहले साल 2021 की 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जिस तरह अराजकता फैलाई गई, उसके बाद से सामान्य सहानुभूति के पात्र रहे किसानों को लेकर लोक विश्वास में दरार पड़ी। दिल्ली में नांगलोई के पास किसानों ने तब जिस तरह सामान्य नागरिकों को निशाना बनाया था, उससे किसान संगठनों के आंदोलन को लेकर लोगों की सोच बदली। रही-सही कसर पूरी कर दी 26 जनवरी 2021 के दिन हुई अराजकता ने पूरी कर दी।

लाल किले पर कब्जे को लेकर हुई किसान हिंसा के बाद तो किसान आंदोलन को विदेश प्रेरित भारत विरोधी आंदोलन मानने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई। किसान संगठनों को यह मान लेना चाहिए कि भारतीय समाज के शहरी हिस्से के सरोकार खेती-किसानी से पहले वाली पीढ़ी की तरह रागात्मक नहीं रहे। शहरी समाज की अपनी चुनौतियां हैं और उनका जीवन संघर्ष भी अपनी तरह का है। दिल्ली जैसे शहर में नौकरी करने वाली बड़ी जनसंख्या दूर-दराज के इलाकों में रहती है। पिछले किसान आंदोलन के दौरान महीनों तक चली दिल्ली की घेरेबंदी के चलते उत्तर प्रदेश और हरियाणा की ओर से आने-जाने वाले लोगों को रोजाना जो दिक्कतें झेलनी पड़ीं, उसके बाद ही किसान आंदोलन को लेकर शहरी लोगों का नजरिया पूरी तरह बदल गया। शायद यही वजह है कि इस बार जारी आंदोलन को लेकर किसानों को लेकर पारंपरिक सहानुभूति नहीं दिख रही। इस आंदोलन को लेकर यह मानने वालों की भी कमी नहीं है कि इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं और राजनीतिक स्तर पर इसे विपक्षी दलों की ओर हवा दी जा रही है। ऐन चुनावों से ठीक पहले आंदोलन का खड़ा होना, उसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा बार- बार सहयोग देना, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव द्वारा इस आंदोलन के बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करना लोगों की इस सोच को बढ़ावा ही दे रही है।

किसान संगठनों के मौजूदा आंदोलन की प्रमुख मांग है, स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करना है। इसी सिफारिश के आधार पर सभी फसलों के लिए एमएसपी घोषित करने की मांग किसान संगठन कर रहे हैं। न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी अपनी हर सभाओं में इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्वामीनाथन समिति ने अपनी रिपोर्ट साल 2006 में दी थी। उसके पूरे आठ साल बाद तक केंद्र में कांग्रेस की अगुआई वाली ही सरकार थी। राहुल गांधी तब भी संसद के सदस्य रहे। तब किसानों को यह सहूलियत देने की राहुल और उनकी कांग्रेस को क्यों नहीं सूझा? आज के आंकड़ों पर ही भरोसा करें तो अगर सभी फसलों पर एमएसपी घोषित कर दी जाए तो भारत सरकार पर करीब 71 लाख करोड़ का दबाव बढ़ेगा।

जबकि भारत का कुल बजट ही 47 लाख करोड़ का ही है। सवाल यह है कि अगर एमएसपी की मांग मान भी ली गई तो भारत 24 लाख करोड़ रूपए कहां से लाएगा। साफ है कि स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को पूरी तरह लागू कर पाना ना तो कांग्रेस की अगुआई वाली सरकार के वश की बात थी और ना ही मोदी सरकार के लिए संभव है। चूंकि आज की राजनीति का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति रह गया है। इसलिए हर राजनीतिक दल का सच अपना-अपना हो गया है। वह सार्वभौम या मूल सत्य पर नहीं टिका रहता। यही वजह है कि कांग्रेस किसानों को अपने दौर का सच नहीं बता रही है। उस सरकार में शामिल ममता और लालू यादव को भी यह सच पता है। लेकिन वे भी इसके मुताबिक अपनी राय ना रखते हुए सिर्फ और सिर्फ मौजूदा केंद्र सरकार को ही किसानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं।

अतीत का किसान आंदोलन सीएए के खिलाफ उभरे आंदोलन के ठीक बाद आया था। तब दोनों ही आंदोलनों का स्वरूप और उसमें सक्रिय लोग समान थे। बाद में इन आंदोलनों की फंडिंग पर भी सवाल उठे। लाल किला कांड के बाद हुई जांच और गिरफ्तारियों से भी पता चला कि विदेशी ताकतें भी इन आंदोलनों के बहाने देश को अस्थिर करने की कोशिश में लगी रहीं। इसी वजह से इस बार के किसान आंदोलन को लेकर देश में गहरी सहानुभूति नहीं दिख रही। देश का एक बड़ा तबका मानने लगा है कि इस आंदोलन का एक मात्र मकसद विपक्षी दलों के लिए आगामी चुनावों में सियासी पिच तैयार करना है। ताकि वे मोदी विरोध में सफल बल्लेबाजी कर सकें। लोग यह भी मानने लगे हैं कि इस आंदोलन का मकसद दिल्ली को बंधक बनाकर देश की छवि भी बिगाड़ना है। यह बात और है कि किसानों की भावना इस तरह से भड़काई गई है कि उन्हें आंदोलन के पीछे के राजनीतिक लक्ष्य नजर नहीं आ रहे।

मारुति जिम्नी ने बर्फ में फंसी लैंड रोवर डिफेंडर और स्कॉर्पियों एन को चुटकियों में निकाल दिया...

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। Maruti Suzuki Jimny को भारतीय बाजार में लॉन्च हुए लगभग एक साल होने वाला है। हालांकि, कंपनी को उम्मीद के मुताबिक कस्टमर बेस नहीं मिला है, लेकिन इसने अपने परफॉरमेंस की बदौलत कई लोगों को आकर्षित किया। हाल ही में जिम्नी का एक वीडियो सामने आया है , जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

Maruti Suzuki Jimny ने बर्फ में किया कमाल

एक हालिया घटना कैमरे में कैद हुई, जब Maruti Suzuki Jimny को Land Rover Defender और Mahindra Scorpio जैसे ऑफ-रोड आइकन को बाहर निकालते देखा गया। ये ऑफरोडर एसयूवी मोटी बर्फ की जगह में फंस गई थीं। ये वीडियो संभवतः जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग के पास कहीं शूट किया गया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

वीडियो में दिखाया गया है कि गुलमर्ग के पंजीकरण नंबर वाली मारुति जिम्नी एसयूवी केवल एक टो स्ट्रैप का उपयोग करके दो एसयूवी को एक-एक करके बाहर निकालती है। ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि Jimny उन दो मॉडलों की तुलना में कहीं अधिक हल्की एसयूवी है, जिसे बचाने में मदद मिली है। जहां जिम्नी एसयूवी का वजन 1,000 किलोग्राम से थोड़ा अधिक है, वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी का वजन लगभग 1,800 किलोग्राम है और लैंड रोवर डिफेंडर का वजन जिम्नी के दोगुने से भी ज्यादा है।

मारुति सुजुकी की जिम्नी एसयूवी को भारतीय बाजार में 5-डोर वर्जन में बेचा जाता है। इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 12.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि टॉप-एंड वर्जन की कीमत 15.00 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। आपको बता दें कि जिम्नी एसयूवी में 4X4 ड्राइवट्रेन स्टैंडर्ड है।

किफायती कीमत में लग्जरी गाड़ी खरीदने वालों के लिए बेस्ट हैं ये ऑप्शन, लिस्ट में बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज सहित शामिल ये नाम

Best Affordable Luxury Cars अगर आप लग्जरी गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि किफायती प्राइस रेंज में कोई दमदार सी गाड़ी मिल जाए तो इस लेख में हम आपके लिए कुछ ऐसी प्रीमियम कारों के लिए लिस्ट लेकर आए हैं जिनमें से आप किसी एक को विकल्प बना सकते हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। लग्जरी गाड़ियों के प्रति अलग ही स्तर की दीवानगी देखी जाती है। ये आम कारों की तुलना में काफी प्रीमियम अनुभव देती हैं और इनमें फीचर्स भी काफी आधुनिक दिए जाते हैं। इस लेख में हम बेस्ट अफॉर्डेबल लग्जरी कारों (Affordable Luxury Cars) की लिस्ट लेकर आए हैं। ये ऐसे लोगों के लिए अच्छा विकल्प बन सकती हैं जो कम से कम दाम में लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं।

यह लग्जरी गाड़ी ऐसे लोगों के लिए परफेक्ट विकल्प बन सकती हैं जिनका बजट 50 लाख रुपये के आसपास है। इस गाड़ी की कीमत 42.80 लाख रुपये एक्सशोरूम से शुरू होती है। इसमें 1332cc का इंजन मिलता है जो 161bhp की पावर और 270 एनएम का टॉर्क निकालकर दे देता है।

इस कार की कीमत 45.34 लाख रुपये एक्सशोरूम से शुरू होती है। इसमें 1984 सीसी की क्षमता वाला इंजन मिलता है जो 320 एनएम का टॉर्क 187.74 बीएचपी की शक्ति पैदा प्रदान करता है। लग्जरी कार में 460 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है।

Volvo S90

Volvo S90 की कीमत 68.25 लाख रुपये एक्सशोरूम से शुरू होती है। इसको सेफ्टी के लिहाज से 5 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग मिली हुई है। गाड़ी में 1969 cc का इंजन दिया गया है जो 350 एनएम का पीक टॉर्क और 246.58 bhp की शक्ति उत्पन्न कर सकता है।

BMW 3 Series Gran Limousine

इसकी कीमत 60.60 लाख रुपये एक्सशोरूम से स्टार्ट होती है। इसमें 400 एनएम का टॉर्क और 254.79 bhp की शक्ति पैदा करने वाला 1998 cc का इंजन दिया गया है। यह गाड़ी 250 किमी/प्रतिघंटा की टॉप स्पीड से चल सकती है।

टीवीएस मोबिलिटी ने मित्सूबिशी कॉर्पोरेशन से मिलाया हाथ, पैसेंजर व्हीकल से लेकर MHE तक की होगी सेल

टीवीएस मोबिलिटी ने एक बयान में कहा इस निवेश का उद्देश्य पैसेंजर कारों कमर्शियल वाहन और मैटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट(MHE) को भारतीय बाजार के अंदर सेल करना है। तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन टीवीएस मोबिलिटी समूह के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है जिसमें बिक्री के बाद सेवा प्रदाता टीवीएस ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस (TASL) में निवेश भी शामिल है।

टीवीएस मोबिलिटी ने एक बयान में कहा इस निवेश का उद्देश्य पैसेंजर कारों कमर्शियल वाहन और मैटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट(MHE) को भारतीय बाजार के अंदर सेल करना है। तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन टीवीएस मोबिलिटी समूह के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है जिसमें बिक्री के बाद सेवा प्रदाता टीवीएस ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस (TASL) में निवेश भी शामिल है।

नई दिल्ली। TVS Mobility ने जापानी कार निर्माता कंपनी Mitsubishi Corporation के साथ ज्वाइंट वेंचर शुरू किया है। इसको लेकर टीवीएस मोबिलिटी ने सोमवार को कहा कि सहयोग के हिस्से के रूप में मित्सुबिशी कॉरपोरेशन की ओर से शुरुआत में 300 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और दोनों पक्ष संयुक्त उद्यम के विकास का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

TVS Mobility ने Mitsubishi Corporation से मिलाया हाथ

टीवीएस मोबिलिटी ने एक बयान में कहा, इस निवेश का उद्देश्य पैसेंजर कारों, कमर्शियल वाहन और मैटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट(MHE) को भारतीय बाजार के अंदर सेल करना है। इसमें कहा गया है कि बिजनेस मॉडल में अगले 3-5 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू हासिल करने की क्षमता होगी। इसके साथ, टीवीएस मोबिलिटी का डीलरशिप व्यवसाय टीवीएस वाहन मोबिलिटी सॉल्यूशन (TVS VMS) में बदल जाएगा जो अपने ग्राहकों को सेवाओं का पूरा पोर्टफोलियो पेश करेगा।

टीवीएस मोबिलिटी के निदेशक आर दिनेश ने कहा-

टीवीएस मोबिलिटी ने भारत में अपने डीलरशिप व्यवसाय के माध्यम से वाहन बाजार की बिक्री, सेवा और वितरण में अग्रणी भूमिका निभाई है। एमसी के साथ यह सहयोग टीवीएस को व्हीकल मोबिलिटी ईकोसिस्टम के लिए समाधानों की एक सीरीज प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

Mitsubishi Corporation का फ्यूचर प्लान

तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन टीवीएस मोबिलिटी समूह के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें बिक्री के बाद सेवा प्रदाता टीवीएस ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस (TASL) में निवेश भी शामिल है। कंपनी किन मॉडल्स को भारतीय बाजार में बेचेगी, इसको लेकर कोई आधिकारिक अभी तक सामने नहीं आई है।

IFEVA™
International Federation of Electric Vehicle Association

Hero Mavric X440 Review: केवल Harley Davidson का बैज नहीं लेकिन फील वही, फैसला आपको करना है

Mavric 440 को हीरो-हार्ले की साझेदारी के बनाया गया है। दोनों मोटरसाइकिलों का इंजन मेन फ्रेम और ब्रेक एक समान हैं। इसमें दिया गया 440-सीसी सिंगल-सिलेंडर एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन सबसे बड़ा है। ये पावरट्रेन 27 बीएचपी और 36 एनएम पीक टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। इसका डिजाइन दृष्टिकोण किसी भी आधुनिक क्लासिक के विपरीत है जिसे आप 2.5 लाख से कम में खरीद सकते हैं।

नई दिल्ली। Hero MotoCorp ने अपनी सबसे प्रीमियम बाइक Mavric 440 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। Harley Davidson X400 पर आधारित ये मोटरसाइकिल प्राइस के मामले में काफी किफायती है। कंपनी ने इसको 1.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जो टॉप वेरिएंट के लिए 2.24 लाख रुपये तक जाती है।

हमारे साथी अनिर्बान मित्रा ने Hero Mavric 440 से देश के पश्चिमी सिरे पर 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की है। आइए, जान लेते हैं कि भुज में हीरो की सबसे प्रीमियम बाइक को चलाकर उन्हे कैसा लगा?

राइडिंग अनुभव

Mavric 440 को हीरो-हार्ले की साझेदारी के बनाया गया है। दोनों मोटरसाइकिलों का इंजन, मेन फ्रेम और ब्रेक एक समान हैं। फिर भी, इसका करेक्टर HD X440 से स्पष्ट रूप से भिन्न है। राइडिंग की बात करें, तो 5 फीट 4 इंच से अधिक लंबे किसी भी व्यक्ति के लिए 803 मिमी की सीट हाइट अच्छा-खासा अनुभव प्रदान करती है।

इंजन

इसमें दिया गया 440-सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन सबसे बड़ा है। ये पावरट्रेन 27 बीएचपी और 36 एनएम पीक टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। एक्सप्रेस वे पर ट्रिपल डिजिट स्वाभाविक रूप से आते हैं, और राइडर मीलों तक 110-120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। कुल मिलाकर, इंजन मजबूत मिड-रेंज टॉर्क के साथ ट्रैक्टेबल है। बाइक में 5,500 आरपीएम पर बाइब्रेश शुरू होता है।

स्पेसिफिकेशन

डुअल-चैनल एबीएस इसमें स्टैंडर्ड रूप से दिया गया है। ब्रेक का प्रभाव भी काफी तेज है। मावरिक 440 में 43-मिमी टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और पीछे प्री-लोड एडजस्टेबल ट्विन कॉइल्स दी गई हैं। ट्यूनिंग काफी हद तक आलीशान है, जो धक्कों और सड़क की उतार-चढ़ाव को आराम से सोख लेती है। हीरो मोटोकॉर्प ने इसके साथ एक्सेसरीज की एक सीरीज डेवलप की है,जिसे ग्राहक अपने उपयोग के अनुसार चुन सकते हैं।

डिजाइन

इसका डिजाइन दृष्टिकोण किसी भी आधुनिक क्लासिक के विपरीत है, जिसे आप 2.5 लाख से कम में खरीद सकते हैं। गोल एलईडी हेडलैम्प के साथ मास-फॉरवर्ड, फ्लेयर्ड मेटल टैंक सिल्हूट को मजबूती प्रदान करता है। इसे छोटे फेंडर के साथ ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है।

मशीन-कट अलॉय व्हील केवल टॉप वेरिएंट के साथ उपलब्ध हैं। पीछे का भाग कुछ अकल्पनीय प्रतीत होता है मानो जल्दबाजी में समाप्त कर दिया गया हो। विशेष रूप से ग्रैब रेल और एग्जॉस्ट, इसके प्रभावशाली डिजाइन को कमजोर कर देते हैं।

आर्थिकी के श्वेत-स्याह पत्र की तस्वीर

डा . जयंतीलाल भंडारी

गौरतलब है कि 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने संबोधन में कहा कि विगत 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है। अब आगामी पांच वर्ष विकसित भारत की बुनियाद के होंगे। दुनिया भारत की युवाशक्ति का दम देखेगी।

भारत के द्वारा वर्ष 2023 में की गई जी-20 की सफल अध्यक्षता से नए आर्थिक लाभों की ऐसी अभूतपूर्व संभावनाएं मिली हैं जिससे इस वर्ष 2024 में भारत से निर्यात, भारत में विदेशी निवेश, भारत में विदेशी पर्यटन और भारत के डिजिटल विकास का नया क्षितिज सामने आते हुए दिखाई देगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के मद्देनजर भारत की अहमियत बढ़ेगी'

इस समय पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले लोग हाल ही में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में मोदी सरकार के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को रफ्तार दिए जाने और संप्रग सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर पेश किए गए श्वेतपत्र तथा कांग्रेस के द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस के माध्यम से मोदी सरकार के 10 वर्षों की विफलताओं पर प्रस्तुत किए गए स्याह पत्र पर विचार मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि जहां मोदी सरकार आर्थिक विकास व स्वरोजगार के विभिन्न मापदंडों पर तेजी से आगे बढ़ी है, वहीं प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में मोदी सरकार अभी यथोचित सफलता से दूर है। वर्ष 2013-14 में भारत की अर्थव्यवस्था मुश्किल के दौर में थी। वह समय संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम वर्ष था। यदि हम संप्रग सरकार के उस समय के आर्थिक परिदृश्य को देखें तो पाते हैं कि भारत के राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति तथा चालू खाते के घाटे में तेज इजाफा हुआ था। स्थिति यह थी कि वर्ष 2012-13 में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 5 फीसदी के करीब था। वृद्धि को गति प्रदान करने के मद्देनजर ऐसी परियोजनाओं को ऋण देने को कहा गया जो उपयुक्त नहीं थीं। परिणामस्वरूप फंसे हुए कर्ज में तेज वृद्धि हुई। उस समय तत्कालीन सरकार भ्रष्टाचार तथा कई घोटालों के आरोपों में घिर गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में 122 दूरसंचार लाइसेंस निरस्त कर दिए। इससे उस दौर के राजनीतिक तथा आर्थिक परिदृश्य का अंदाजा लगाया जा सकता है।

इतना ही नहीं, कई घोटालों और समस्याओं से घिरी संप्रग सरकार समय पर जरूरी निर्णय नहीं ले सकी। भारत लगभग मुद्रा संकट के कगार पर पहुंच गया था। दूसरी ओर वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार (एनडीए) ने आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने को प्राथमिकता दी। राजकोषीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत प्रतिबद्धता का मजबूत संदेश दिया। साथ ही ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के जरिए शक्ति संतुलन को लेनदारों के पक्ष में कर दिया। इससे ऋण संस्कृति में सुधार हुआ है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उल्लेखनीय पूंजी डालने से दोहरी बैलेंस शीट के घाटे को दूर करने में मदद मिली है। निश्चित रूप से एनडीए सरकार ने ऐसे कई तरह के सुधारों को अंजाम दिया जिनसे कारोबारी सुगमता बढ़ाई जा सके। रिजर्व बैंक ने मुद्रा और विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को लेकर वृहद आर्थिक स्थिरता को मजबूत बनाने के उपाय किए। लगातार कर सुधारों से भारत को अपने कर-जीडीपी अनुपात में सुधार करने में मदद मिली है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से उद्योग-कारोबार को लाभ हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में बुनियादी ढांचे के निर्माण में आई क्रांति अहम भूमिका निभा रही है। पिछले 9 साल में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उद्योग-कारोबार को आसान बनाने के लिए 1500 पुराने कानूनों और 40 हजार अनावश्यक अनुपालन को समाप्त किए जाने की अहम भूमिका है। इस समय भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए मेक इन इंडिया 2.0, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए तकनीकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए उद्योग 4.0, स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना परियोजना के लिए पीएम गति शक्ति और उद्योगों को डिजिटल तकनीकी शक्ति प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया जैसी सफल पहलों से भारत चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

गौरतलब है कि 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने संबोधन में कहा कि विगत 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है। अब आगामी पांच वर्ष विकसित भारत की बुनियाद के होंगे। दुनिया भारत की युवाशक्ति का दम देखेगी। स्टार्टअप, पेटेंट और सेमीकंडक्टर सहित विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत का परचम दुनिया में फहराते हुए दिखाई देगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भी एकमत से कहा जा रहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक दुनिया का विकसित देश बनते हुए दिखाई दे सकता है। पिछले दिनों वित्त मंत्रालय की तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी विस्तृत रिपोर्ट 'द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू' में कहा गया है कि अगले तीन साल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और भारत आर्थिक आकार के लिहाज से अमेरिका व चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना महामारी और उसके ठीक बाद भू-राजनीतिक उथल-पुथल से जहां दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दो प्रतिशत की विकास दर हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया को आश्चर्यचकित करते हुए आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में भी सात प्रतिशत की विकास दर हासिल कर सकती है। रिपोर्ट में यह बात भी रेखांकित की गई है कि पिछले एक दशक में सरकार के साहसिक आर्थिक निर्णयों ने देश की आर्थिक बुनियाद को मजबूत बना दिया है। ऐसे में कृषि से लेकर मैन्यूफैक्चरिंग और डिजिटल सेवा की बदौलत सर्विस सेक्टर में मजबूती आई है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक रणनीति से इस समय भारत के पास टिकाऊ विकास के अभूतपूर्व अवसर हैं। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर भारत को विशेष अहमियत, अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियों के साथ भारत की मित्रता, तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार के कारण दुनिया के अधिकांश देशों की भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) की ललक, प्रवासी भारतीयों के द्वारा वर्ष 2023 में 125 अरब डॉलर से अधिक धन भारत को भेजने के साथ नए आर्थिक तकनीकी विकास के लिए बढ़ते कदम, चीन के प्रति बढ़ती नकारात्मकता के मद्देनजर भारत नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभरकर सामने आया है। इसके साथ-साथ दुनिया में मजबूत लोकतंत्र और स्थिर सरकार के रूप में भारत की पहचान, भारत के शेयर बाजार का दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ना, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, देश में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, बड़े पैमाने पर पूंजीगत खर्च, गैर जरूरी आयात में कटौती और अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों से उबरने की क्षमता देश के टिकाऊ विकास की बुनियाद बन सकती हैं।

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत के द्वारा वर्ष 2023 में की गई जी-20 की सफल अध्यक्षता से नए आर्थिक लाभों की ऐसी अभूतपूर्व संभावनाएं मिली हैं जिससे इस वर्ष 2024 में भारत से निर्यात, भारत में विदेशी निवेश, भारत में विदेशी पर्यटन और भारत के डिजिटल विकास का नया क्षितिज सामने आते हुए दिखाई देगा। जी-20 से दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के मद्देनजर भारत की अहमियत बढ़ेगी। प्राकृतिक संपदा संपन्न अफ्रीकी संघ को जी-20 में शामिल कराकर भारत ने इन देशों से नए आर्थिक लाभों की उम्मीदों को बढ़ाया है। इससे अब भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भी तेजी से बढ़ेगा। एनडीए का श्वेत पत्र अधिक प्रासंगिक, अधिक वास्तविक और अधिक विकासपरक है।

संपादक की कलम से

ये 'कमल' खिलाते कांग्रेसी

यह लोकसभा चुनाव का मौसम है, लिहाजा प्रत्येक राजनीतिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं, दूसरी तरफ भाजपा का कुनबा विस्तृत होता जा रहा है। उसकी चुनावी चुनौती भी 'अपराजेय' लगती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी बिखर रही है, जिसके नेता पार्टी छोड़ कर भाजपा या अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का राजनीतिक और वैचारिक घर टूट रहा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण और चिंतित सरोकार है। सरोकार इसलिए है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 12 करोड़ मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था। यह कोई सामान्य जनाधार नहीं है, लिहाजा कांग्रेस का चिंतित विश्लेषण करना आज मौजू है। ताजा खबर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 9 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की है। फिलहाल अटकलें हैं कि वह और उनके सांसद-पुत्र नकुल नाथ कांग्रेस का 'हाथ' छोड़ कर भाजपा का साथ देने जा रहे हैं। बिना आग के धुआं नहीं होता! यह उक्ति फिजूल नहीं है। चूंकि नकुल नाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस का नाम और चुनाव चिह्न हटा दिए हैं। ऐसा कई कांग्रेस विधायकों और पूर्व विधायकों ने भी किया है। सोशल मीडिया पर 'जय श्री राम' और 'परिवारजनों के साथ' लिखा गया है।

प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधनों में अक्सर 'परिवारजनों' कहते रहे हैं, लिहाजा यह भी पुख्ता संकेत हो सकता है। अचानक छिंदवाड़ा से दिल्ली आए कमलनाथ ने इन अटकलों का खंडन तक नहीं किया है। वह 'इस तरफ या उस तरफ' की भाषा बोल रहे हैं। मीडिया को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि जैसे भी कोई खबर होगी, सबसे पहले आपके साथ साझा करूंगा।' बहरहाल कमलनाथ ने 50 साल से अधिक समय तक कांग्रेस के साथ रहकर राजनीति की है। यकीनन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें अपना 'तीसरा बेटा' मानती थीं। यदि अब 77 साल की उम्र में वह राजनीतिक पाला बदलते हैं और बेटे का संसदीय करियर सुरक्षित करना चाहते हैं, तो वे दोनों कांग्रेस से भाजपा में आ सकते हैं। यह पालाबदल कांग्रेस के लिए 'आत्मघाती' साबित हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस आलाकमान इसे 'आंतरिक लोकतंत्र' करार दे रहा है। कमलनाथ नया उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन अशोक चव्हाण, गुलाम नबी आजाद, एसएम कृष्णा, विजय बहुगुणा, दिगंबर कामत, मुकुल संगमा, किरन रेड्डी, एन. वीरेन सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नारायण राणे आदि 13 कांग्रेसी मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ कर भाजपा का 'कमल' खिला चुके हैं। बुनियादी सवाल है कि आखिर इतने वरिष्ठ और परंपरागत कांग्रेस नेता पार्टी को अलविदा कहने को विवश क्यों हो रहे हैं? सभी को प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आयकर विभाग के खौफ नहीं हैं। दरअसल यह कांग्रेस के भीतर की हताशा और चुनाव न जीतने की संभावना एं ही हैं कि कांग्रेसी 'अपना घर' छोड़ रहे हैं।

भाजपा में संभावनाएं और राजनीतिक आयाम बेहद व्यापक हैं। जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, उन्हें या तो राज्यसभा में भेजा गया है अथवा राज्य सरकारों में मंत्री या केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस कमलनाथ को राज्यसभा में भेजकर मना नहीं सकी। भाजपा ने हिमंता बिस्व सरमा, पेमा खांडू और माणिक साहा तो क्रमशः असम, अरुणाचल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बना दिए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने बीते सप्ताह ही कांग्रेस छोड़ी है और भाजपा के राज्यसभा सांसद बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस में किसी भी स्तर पर, अपने वरिष्ठ चेहरों को, मनाने की कवायद तक नहीं की गई। भाजपा तो तैयार बैठी है। यही राजनीति है। यदि छिंदवाड़ा से कमलनाथ भाजपा में आ जाते हैं, तो भाजपा को वह लोकसभा सीट जीतना भी तय हो जाएगा, जिसे आज तक भाजपा कभी भी हासिल नहीं कर सकी है। भाजपा की चुनावी रणनीति यही है कि एक-एक सीट सुनिश्चित कर वह 370 के 'टारगेट' तक पहुंचना चाहती है। कांग्रेस 'इंडिया' के दलों को संजोने में नाकाम रही है। आत्मचिंतन से रास्ता निकल सकता है कि घर को जोड़ कर कैसे रखा जा सकता है।

राय

सुक्खू सरकार का बजट

सुक्खू सरकार का बजट खुद से बात, खुद से मुलाकात और खुद से प्रण लेता हुआ सुर्खियां बटोर गया, भले ही हिमाचल के प्रश्न और प्रश्नों के आधार पर आर्थिक दिक्कतें परीक्षा ले रही हैं। प्रदेश जिसके कंधों पर 87 हजार करोड़ का ऋण हो तथा इसी साल राजकोषीय घाटा दस हजार करोड़ के पार हो, उसके बजट के सुखद पहलू लिखने कोई आसान नहीं। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजटीय प्रमाणिकता के साथ वादों और इरादों की झड़ी लगा रहे हैं, तो इसका व्यावहारिक पक्ष भी समझना होगा, फिर भी इसके गणित के बाहर ऐसा बहुत कुछ है, जिससे प्रदेश अपनी लोक कल्याणकारी नीतियों, विकास के दायित्व, किसानों-बागबानों के प्रति समर्पण, कर्मचारियों की अपेक्षाओं तथा जनप्रतिनिधियों की हसरतों को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। शहरी और ग्रामीण निकायों के चयनित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करके मुख्यमंत्री राजनीतिक बिरादरी का मान-सम्मान बढ़ा रहे हैं। बजट के माध्यम से विधायक व ऐच्छिक निधि में हो रहा इजाफा जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्व की संरचना में आत्मबल दे रहा है। इतना ही नहीं, नगर निगम क्षेत्रों में विधायक प्राथमिकताओं को अमल में लाने के लिए नई व्यवस्था के तहत फंड मुहैया हो रहा है। कहना न होगा कि सुक्खू का बजट आर्थिक दस्तकारी करते हुए राज्य के लिए आत्मनिर्भरता के लक्षण बटोर रहा है और इसी के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकताएं तय हो रही हैं। पर्यटन के जरिए राज्य की उम्मीदों को परवान चढ़ाने के लिए सुक्खू सरकार तेरह करोड़ की लागत से नौ हेलिपोर्ट स्थापित करने के लिए अंतिम चरण में पहुंच रही है, तो इसी तरह कनेक्टिविटी के आधार को पुख्ता करती हुई प्राथमिकता गगल एयरपोर्ट विस्तार की हर मंजिल को दुरुस्त कर रही है। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के मकसद से एयरपोर्ट विस्तार की हर कड़ी पर सुक्खू सरकार बुलंदी से काम कर रही है और वचनबद्धता को दोहरा रही है।

कुफरी के नजदीक हासन घाटी में स्काई वॉक ब्रिज तथा ईको टूरिज्म के तहत 93 साइट्स को निजी सहयोग से शुरू करने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। पांच नए पर्यटक स्थलों की पहचान व इनके विकास को लेकर बजट ने जो छलांग लगाने की कोशिश की है, उसके परिणामस्वरूप हिमाचल का मानचित्र बदल सकता है। बजट प्राकृतिक खेती की ओर एक नया संकल्प लेते हुए 36 हजार किसानों के खेतों को बदलने का आश्वासन दे रहा है, तो किसानों को बाड़ लगाने की सबसिडी देने की घोषणा हो रही है। सुक्खू सरकार राज्य को ग्रीन बनाने की दिशा में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में वृद्धि करने जा रही है। ई-टैक्सी पर चालीस फीसदी सबसिडी के माध्यम से दस हजार परमिट दिए जाएंगे। बजट का लोक कल्याणकारी हिस्सा मुखातिब है और इस संदर्भ में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, विधवाओं के नाबालिग बच्चों को हजार रुपए की आरडी तथा शादियों के लिए सरकारी डिपुओं से मिलेगा राशन। सुक्खू सरकार कैंसर प्रतिष्ठान के रूप में हमीरपुर मेडिकल कालेज को सौ करोड़ का प्रावधान कर रही है, लेकिन इसी दृष्टि से केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल परिसर का कोई उल्लेख न होना हैरान करता है। धर्मशाला में परिसर के पक्ष में जारी आंदोलन इतनी उम्मीद तो कर ही सकता है कि कुल 58444 करोड़ के बजट से केंद्रीय विश्वविद्यालय की जदरांगल में स्थापना को तीस करोड़ मिल ही जाएंगे। बजट शिक्षा, अधोसंरचना, स्वास्थ्य सेवाओं व जलशक्ति परियोजनाओं पर पूरी तरह मेहरबान है, तो सभी पंचायतों में आधुनिक पुस्तकालयों की दिशा में प्रयासरत है। हालांकि घाटे के लेखे-जोखे में राज्य का बजट कसीदागिरी कर रहा है, फिर भी देखना यह होगा कि आर्थिक विषमताओं और दबावों के बीच सुक्खू सरकार कितनी किफायत कर पाती है।

शव संवाद-31

सोशल मीडिया पांव पर चलता नहीं, कंधे पर सवार हो जाता है। इसे कितने कंधे चाहिए, गिन नहीं पाता। आश्चर्य यह कि सोशल मीडिया के विचार, तर्क और लय किसी को भी बुद्धिहीन कर सकते हैं, फिर भी लोग इस माध्यम से अपनी बुद्धि को आजमाने का मौका नहीं चूकते। बुद्धिजीवी मुगालते में था कि वह सोशल मीडिया का चैंपियन बन जाएगा और दिमाग के खेल में सब पर भारी पड़ेगा। शुरुआत में ऐसा हुआ, लेकिन बुद्धिजीवी को शीघ्रही मालूम हो गया कि यहां बुद्धि की कोई औकात नहीं, जो चल गया वही स्वीकार्य सामान है। सोशल मीडिया में विचार या संदेश एक उत्पाद है, जिसकी मार्केटिंग होती है। वैसे भी समाज अब एक उत्पाद ही तो है जिसे सोशल मीडिया के संदेश बना और पका रहे हैं। हर उत्पाद के लिए कीमत का एक टैग जरूरी है और इसीलिए आज का मीडिया और सोशल मीडिया समाज को सियासत का उत्पाद मानकर टैग लगा रहे हैं। कभी सामाजिक ऊर्जा से निकलती थी दूर तक चलने वाली राजनीति, लेकिन अब सियासत की क्षमता में समाज चलता है। देश को चलाने के लिए सोशल मीडिया अब अवतार है। किसी का करिश्मा तो किसी की धार है। सोशल मीडिया अपने में जन्म दिन और अपने में मृत्यु दिवस लेकर चलता है। आपको नेहरू का हाल पूछते गांधी मिल जाएंगे और गांधी को पटेल बता नहीं पाएंगे कि देश में आज वह क्यों चलाए जा रहे हैं। ऐसे में बुद्धिजीवी करे भी तो क्या। पूजा के लिए समाज किसी विवादित मस्जिद को ढूंढ रहा है, तो अपनी अपनी जाति में ही जन प्रतिनिधि खोज रहा है। उसे विश्वास है कि एक दिन जातियों का हिसाब उसके लिए उसके ही नैन नक्श का विधायक सामने ले आएगा, तब वह सोशल मीडिया पर बता पाएगा कि उसकी जाति भी इसमें चलती है। सोशल मीडिया की मुक्का-मुक्की में विचार कितना प्रधान, यह अंदाजा मात्र एक संदेश से हो जाता है।

बुद्धिजीवी के रिश्ते जब जब मरते हैं, सोशल मीडिया पर उसका संदेश अमर हो जाता है। उसका विश्वास है कि आइंदा भी जब कभी वह अपने किसी रिश्तेदार की मौत को सोशल मीडिया पर बताएगा, सारा समाज आंसू बहाएगा। एक दिन वह अपनी ही मौत का संदेश बना बैठा और अपनी तमाम असफलताओं को छिपाते हुए सोशल मीडिया पर कहने लगा कि बुद्धिजीवी की मौत पर उसे अफसोस है। वह खुद को सोशल मीडिया पर मार रहा था, लेकिन प्रतिक्रिया में जाने अनजाने भी गुणगान करने लगे। पहली बार उसने देखा कि भारत में एक अकेला मौत का संदेश सब पर भारी है। सब पर भारी पड़ने के लिए एक अदद मौत का संदेश काफी है। बुद्धिजीवी की लड़ाई अपने ही संदेश से थी, जो मरने की झूठी सूचना को अपनी जीत में बदल रहा था। बैठे बिठाए यह संदेश एक जीवित बुद्धिजीवी को अमर बना रहा था, जबकि सही और तथ्यपूर्ण सूचनाएं आजकल मरती ही मीडिया के कारण हैं। बुद्धिजीवी ने तय किया कि सोशल मीडिया में संदेशों के शवों को हरिद्वार पहुंचाएगा। ये सारे संदेश मरे क्योंकि देश की जनता मरने की खबर पर ही जिंदा है।

किसी ने सोशल मीडिया पर कहा था कि विपक्ष का गठबंधन सशक्त होगा, लेकिन जनता ने इस संदेश को मार दिया। किसी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे देश में चलने चाहिएं, जनता ने इन्हें भी निपटा दिया। फिर संदेश चला कि किसान को उसका हक मिले, लेकिन लोगों ने उसकी उगाई दाल-सब्जी खाकर इस संदेश को भी मार दिया, लेकिन जिंदा संदेशों में जातियों का टकराव, धर्म का उन्माद, सरकारों के जुमले, अफसरशाही के हमले जिंदा थे। अंततः बुद्धिजीवी ने अपनी ही मौत के फर्जी संदेश की जिंदा हालत पर पहली बार प्रहार किया। वह बार-बार कोशिश करता, मगर उसकी मौत की अफवाह का संदेश जनता का प्रश्रय पा रहा था। संदेश चीखने लगा। उसे सुनकर भारत की जनता विश्वस्त थी कि बुद्धिजीवी जरूर मरा होगा और मरी होगी वह भावना जो देश में विशुद्ध लोकतंत्र के सपने, सत्ता के शुद्ध आचरण और मतदान के आत्मसम्मान के बारे में चिंतित हैं। सोशल मीडिया के प्रभाव से जहां राष्ट्र के हितैषी, देश के लिए और जनता की आंखें खोलने के मुद्दे मर रहे थे, वहां सोशल मीडिया एक अफवाह के जरिए ही सही, बुद्धिजीवी के मरने की खबर पर जिंदा रहना चाहता था। -क्रमशः

निर्मल असो

विचार

केंद्र-राज्यों के बिगड़ते वित्तीय संबंध

भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भारतीय संविधान विभिन्न वित्तीय संसाधनों को केंद्र तथा राज्यों को प्रदान करता है। संविधान केंद्र को सशक्त करने की बात करता है'

केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय ग्रांट एवं सहायता के ऊपर हमेशा टकराव होता रहा है। हाल ही में दक्षिण भारत के दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केन्द्रीय सरकार पर राज्यों को वित्त देती बार भेदभाव का आरोप लगाया है। इसी सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के खिलाफ दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना दिया। केरल सरकार ने इसके संबंध में उच्चतम न्यायालय में केस दर्ज भी किया है जिसमें कहा है कि केंद्र सरकार राज्य को वित्त/ऋण देने में सीमाओं को लगा रही है जिससे उसे कर्मचारियों के वेतन तक देने में कठिनाई हो रही है। कर्नाटक के एक एमपी ने तो केंद्र के अंतरिम बजट में कम बजट देने पर कहा कि अगर केंद्र सरकार दक्षिणी राज्यों से ऐसे ही भेदभाव करती रही तो दक्षिणी राज्यों को मजबूरन अलग राष्ट्र की मांग उठानी पड़ेगी। इस वक्तव्य की काफी आलोचना हुई है। इस तरह का टकराव ज्यादा उस समय बढ़ जाता है, जब केंद्र में अलग विचारधारा की सरकार होती तथा राज्यों में अलग राजनीतिक दल की सरकार। परंतु एक संघीय सरकार के सुचारू कामकाज के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान में ग्रांट तथा ऋण देने का प्रावधान रखा गया है ताकि केंद्र सरकार उन राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करे जो मुश्किल दौर में हों, ताकि विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास हो सके।

केंद्रीय सरकार का ग्रांट एवं ऋण देने में अपना प्रभुत्व है। केन्द्रीय सरकार की दलील है कि राज्य सरकारें ग्रांट तथा ऋण के प्रयोग में वित्तीय लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतती हैं। बहुत सी राज्य सरकारें सहायता अनुदान, ऋण और ओवरड्राफ्ट के ऊपर ही निर्भर रहती हैं और किसी हद तक उनका प्रदर्शन ठीक नहीं है। वे अपने संसाधन उत्पन्न नहीं करती तथा मित्तव्ययिता पर ध्यान नहीं देती और ओवरड्राफ्ट को नियमित ऋण में बदलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहती हैं। इससे मुद्रास्फीति का दबाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। राज्यों को ध्यान देना चाहिए कि नियोजन का खर्चा वास्तव में संसाधन उत्पन्न कर तथा उनका सही प्रबंध से करना चाहिए तथा ओवरड्राफ्ट के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। राज्य अनुत्पादक खर्चे या खराब लक्षित सब्सिडी के वित्तपोषण के लिए लापरवाही से उधार लेता है, जिससे विकास के लिए धन की उपलब्धता कम हो जाती है और राष्ट्रीय आय को नुकसान होता है। राज्यों का कर्ज देश की क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करता है। अगर कोई राज्य कर चुकाने में चूक करता है तो देश की प्रतिष्ठा संबंधी समस्या पैदा होती है और पूरे भारत की वित्तीय स्थिरता खतरे में डाल दी जाती है। इसलिए राज्यों को किसी स्रोत से ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसमें केंद्र पूरे देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखता है तथा अनुच्छेद 293 (4) के तहत इसकी सीमा तय करता है। केंद्र सरकार राज्यों के उधार, ऋण और घाटे पर सीमा के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता लाता है। राज्यों की स्वायत्तता की मांग देश की एकता और अखंडता को प्रभावित कर सकती है, इसीलिए संविधान केंद्र को सशक्त करने को कहता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि राज्य सरकारों को पहले ही बहुत स्वायत्तता दी गई है। उनका अपने राज्य में बहुत से क्षेत्रों पर नियंत्रण है।

कई बार केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों को ग्रांट तथा ऋण देने के नाम पर कंजूस होती हैं, जिससे राज्य सरकारें हमेशा डरी रहती हैं। इसीलिए केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों पर कुछ राज्यों ने कमेटियां बनाईं जिसमें जेके

थावराज कमेटी को केरल सरकार ने, राजा मन्नार कमेटी 1971 को डीएमके सरकार तमिलनाडु ने 1978 में, केंद्र-राज्य संबंधों पर आलेख पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनाया। राज्य सरकारें बार-बार केंद्र-राज्य संबंधों, विशेष तौर पर वित्तीय संबंधों की विस्तृत समीक्षा की मांग करती रहती हैं। 1983 में केंद्र और राज्यों के संबंध बहुत ही नाजुक स्थिति में थे। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य सम्बन्धों पर 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। हालांकि उस समय आठवां वित्त आयोग श्री वाईबी चवन की अध्यक्षता में कार्य कर रहा था। सरकारिया आयोग ने संवैधानिक, विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं पर केंद्र.-राज्यों के संबंधों पर 1987 में रिपोर्ट पेश की जिसमें 247 सुझाव दिए थे, जिसमें से 180 सुझाव सरकार ने मान कर लागू भी कर दिए, परंतु देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को संरक्षित रखा।

भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भारतीय संविधान विभिन्न वित्तीय संसाधनों को केंद्र तथा राज्यों को प्रदान करता है। परंतु जो भी हो, संविधान अपने आप ही केंद्र को वित्तीय सशक्त करने की बात करता है, जो टकराव का मुख्य कारण है। केंद्र पर निर्भर रहना, राज्यों को मान्य नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कहा था कि सशक्त केंद्र उतना ही जरूरी है, जितने सशक्त और स्वायत्त राज्य हैं। स्वतंत्रता के बाद, केंद्र अपने कार्यों का प्रसार इस प्रकार कर रहा है कि राज्य उन पर निर्भर रहें। केंद्र सरकार अनावश्यक रूप से बहुत से विभागों का कार्य कर रही है जो राज्य के विषय हैं। केंद्र को कम काम करने के लिए ज्यादा वित्तीय साधन हैं और राज्यों को बहुत से महत्वपूर्ण काम करने होते हैं और वित्तीय साधन कम हैं। केंद्र के वित्तीय साधन बहुत ही लोच वाले हैं तथा राज्यों के साधन लोच रहित हैं। इसलिए राज्यों को केंद्र पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। केंद्र सरकार का इस पर कहना है कि केंद्र सरकार के दायित्व भी बढ़े हैं जिसके लिए केंद्र को ज्यादा वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। राज्य सरकारों का कहना है कि महंगाई केंद्र की नीतियों से बढ़ती है, नतीजतन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एवं वेतनमान बढ़ जाते हैं, केंद्र सरकार के संसाधन बहुत हैं, वह तो इसका खर्चा वहन कर लेती है, परंतु राज्य की सरकारें वहन नहीं कर पाती।

सत्यपाल वशिष्ठ

रिटर्न से ज्यादा मूल सुरक्षित रखने में है लोगों की रुचि

जानें भारत में अपने पास कितनी नकदी रखते हैं लोग

परिवहन विशेष न्यूज

आरबीआइ की तरफ से जारी तीन वर्ष के बचत आंकड़ों का एक आकलन कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह ने जारी किया है। उनका कहना है कि लोगों के बीच निवेश के बारे में पूरी जानकारी का नहीं होना एक बड़ी अड़चन है। ज्यादातर घरेलू बचतकर्ताओं को बाजार की अस्थिरता से निश्चित रिटर्न पसंद है। 94 फीसद लोगों ने फिक्स्ड आय वाले स्कीमों में पैसा लगाया हुआ है।

नई दिल्ली। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के बाद शेयर बाजार (Stock Market) और म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है लेकिन भारत में बचत की मूल तस्वीर में बहुत बदलाव अभी भी नहीं आया है। आरबीआइ (RBI) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान घरेलू बचत की कुल राशि का 84 फीसद हिस्सा फिक्स्ड रिटर्न वाली स्कीमों (बैंक जमा योजना आदि) में लगाया गया है जबकि 10 फीसद से ज्यादा राशि लोगों ने नकदी के तौर पर घरों में रखा हुआ है।

इस आधार पर यह माना जा रहा है कि आम जनता के लिए अभी भी ज्यादा रिटर्न से ज्यादा मूल राशि को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है। इस अवधि में भारत ने जितनी राशि बचत की गई है उसका सिर्फ 6.1 फीसद हिस्सा ही शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड बाजार में डाला गया है।

लोगों में जानकारी का नहीं होना एक बड़ी अड़चन

आरबीआइ की तरफ से जारी तीन वर्ष के बचत आंकड़ों का एक आकलन कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह ने जारी किया है। उनका कहना है कि लोगों के बीच निवेश के बारे में पूरी जानकारी का नहीं होना एक बड़ी अड़चन है। ज्यादातर घरेलू बचतकर्ताओं को बाजार की अस्थिरता से निश्चित रिटर्न पसंद है। महंगाई दर से कम रिटर्न हासिल कर रहे हैं लेकिन उनके लिए रिटर्न से ज्यादा सुविधा, कर-छूट को पसंद करते हैं।

94 फीसद लोगों ने फिक्स्ड आय वाले स्कीमों में लगाया पैसा

94 फीसद लोगों ने फिक्स्ड आय वाले स्कीमों में पैसा लगाया हुआ है जबकि सिर्फ 6 फीसद ने दूसरे निवेश विकल्पों को आजमाया है।आरबीआइ के डाटा के मुताबिक उक्त तीन वित्त वर्षों में कुल बचत राशि का 36.8 फीसद हिस्सा (31.65 लाख करोड़ रुपये) बैंक जमा में, 20.1 फीसद हिस्सा (17.28 लाख करोड़ रुपये) पेंशन व पीएफ में, 18.2 फीसद (15.69 लाख करोड़ रुपये) बीमा में, 10.3 फीसद (8.89 लाख करोड़ रुपये) नगदी में और और 7.9 फीसद (6.83 लाख करोड़ रुपये) छोटी बचत स्कीमों में निवेश किया गया।

जबकि शेयर बाजार में 1.3 फीसद (1.10 लाख करोड रुपये) और म्यूचुअल फंड में 4.7 फीसद (4.03 लाख करोड़ रुपये) निवेश किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि 10 फीसद से ज्यादा राशि नगदी में है जिसमें कोई रिटर्न नहीं है।

लग्जरी गुड्स बनाने वाली दुनिया की टॉप-100 कंपनियों में 6 भारतीय नाम भी शामिल, इस कंपनी ने तो...

इस सूची में मालाबार गोल ड को 19वां स्थान मिला है। इसके बाद टाटा ग्रुप की इकाई टाइटन कंपनी को 24वां स्थान मिला है। वहीं आभूषण विनिर्माता कल्याण ज्वेलर्स और जॉय अलुक्कास को डेलॉयट वैश्विक लग जरी सामान सूची 2023 में क्रमश: 46वां और 47वां स्थान मिला है। इस सूची में शामिल अन्य दो भारतीय कंपनियां सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स और थंगामायिल ज्वेलरी हैं

मुंबई। हीरे जवाहरात और आभूषणों की बात हो और भारतीय कंपनियों का परचम न लहराए ऐसा कैसे संभव है। जी हां, लग्जरी सामान (Luxury Goods) बनाने वाली दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों की लिस्ट में भारत की भी 6 कंपनियां शामिल हैं। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और टाइटन के साथ ही चार अन्य भारतीय आभूषण कंपनियां इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही हैं।

इस सूची में मालाबार गोल्ड को 19वां स्थान मिला है। इसके बाद टाटा ग्रुप की इकाई टाइटन कंपनी को 24वां स्थान मिला है। वहीं आभूषण विनिर्माता कल्याण ज्वेलर्स और जॉय अलुक्कास को 'डेलॉयट वैश्विक लग्जरी सामान सूची 2023' में क्रमशः 46वां और 47वां स्थान मिला है। इस सूची में शामिल अन्य दो भारतीय कंपनियां सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स और थंगामायिल ज्वेलरी हैं, जिन्हें क्रमशः 78वां और 98वां स्थान मिला। विविध क्षेत्रों में काम करने वाली फ्रांस की लक्जरी कंपनी एलवीएमएच इस सूची में सबसे ऊपर है।

2023 में 4 अरब डॉलर का राजस्व कमाने वाली कोझिकोड स्थित मालाबार पहली बार इस सूची में शामिल हुई है जबकि टाइटन की कमाई 3.67 अरब डॉलर रही।

घरेलू ब्रांडों का उदय लग्जरी सामान बाजार की उभरती गतिशीलता को दिखाता है। डेलॉइट ने सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि जैसे-जैसे घरेलू अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और उपभोक्ता प्राथमिकताएं विकसित हो रही हैं, देश के लग्जरी बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा रही है, जो इन ब्रांडों की वैश्विक मान्यता में योगदान दे रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में लग्जरी की मांग और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे घरेलू ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। शीर्ष 100 लग्जरी सामान विक्रेताओं ने 2023 में 347 अरब डॉलर का कारोबार किया, जो सालाना आधार पर 13.4 प्रतिशत की वृद्धि है।

सोना हुआ महंगा तो चांदी हुई सस्ती, खरीदारी से पहले चेक करें नए दाम

सोना-चांदी के नए भाव जारी हो गए हैं। आज जहां एक ओर सोने की वायदा कीमत में बढ़ोतरी रही तो वहीं चांदी की वायदा कीमत में गिरावट दर्ज हुई है। सोमवार को सोने की कीमत 170 रुपये उछलकर 62048 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमत सोमवार के कारोबारी दिन 569 रुपये गिरकर 71543 रुपये प्रति किलोग्राम रह गयी।

नईदिल्ली। सोना-चांदी के नए भाव जारी हो गए हैं। सोने की कीमत में उछाल दर्ज हुआ है। वहीं, चांदी पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले आज सस्ती हो गई है।

आज जहां एक ओर सोने की वायदा कीमत में बढ़ोतरी रही तो वहीं चांदी की वायदा कीमत में गिरावट दर्ज हुई है।

सोना 250 रुपये चढ़ा; चांदी 500 रुपए लुढ़की

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने की कीमत 250 रुपये चढ़कर 62,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले कारोबारी दिन सोना 62,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटी के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ₹विदेशी बाजारों से सकारात्मक रुख लेते हुए दिल्ली के बाजारों में सोने की हाजिर कीमतें (24 कैरेट) 250 रुपये बढ़कर 62,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही हैं।₹

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, कॉमेक्स पर सोना हाजिर 2,020 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद से 7 अमेरिकी डॉलर अधिक है।

हालांकि, चांदी गिरावट के साथ 23.09 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर थी, जबकि पिछले कारोबार में यह 23.39 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई थी। आज के कारोबारी दिन चांदी 500 रुपये टूटकर 76,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

सोने की वायदा कीमत में उछाल

सोमवार को सोने की कीमत 170 रुपये उछलकर 62,048 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 170 रुपये या 0.27 प्रतिशत बढ़कर 62,048 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 13,340 लॉट का कारोबार हुआ।

वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना वायदा 0.38 प्रतिशत बढ़कर 2,031.70 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया।

चांदी की वायदा कीमत में गिरावट

चांदी की कीमत सोमवार को 569 रुपये गिरकर 71,543 रुपये प्रति किलोग्राम रह गयी।

22 फरवरी को खुलेगा GPT हैल्थकेयर का IPO, प्राइस बैंड 177-186 रुपये प्रति शेयर हुआ तय

जीपीटी हेल्थकेयर लिमिटेड ने सोमवार को अपने आईपीओ के लिए 177-186 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि शुरुआती शेयर-बिक्री 26 फरवरी को समाप्त होगी और एंकर निवेशकों के लिए बोली 21 फरवरी को एक दिन के लिए खुलेगी। जीपीटी हेल्थकेयर में 2.6 करोड़ शेयर या 32.64 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली बनियानट्री कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रही है।

नई दिल्ली। जीपीटी हेल्थकेयर लिमिटेड ने सोमवार को अपने आईपीओ के लिए 177-186 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 22 फरवरी को खुलेगा।

आईएलएस हॉस्पिटल्स ब्रांड के तहत मिड साइज मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों का संचालन और प्रबंधन करती है।

शुरुआती शेयर-बिक्री 26 फरवरी को होगी खत्म

कंपनी ने एक बयान में कहा कि शुरुआती शेयर-बिक्री 26 फरवरी को समाप्त होगी और एंकर निवेशकों के लिए बोली 21 फरवरी को एक दिन के लिए खुलेगी।

आईपीओ कुल मिलाकर 40 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों का फ्रेश इशू और निजी इक्विटी फर्म बनियानट्री ग्रोथ कैपिटल द्वारा 2.6 करोड़ इक्विटी शेयरों के ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है।

कोलकाता स्थित जीपीटी हेल्थकेयर में 2.6 करोड़ शेयर या 32.64 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली बनियानट्री कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रही है।

फ्रेश इशू 30 करोड़ रुपये की आय का उपयोग ऋण के भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

आईपीओ मूल्य दायरे के निचले स्तर पर 501.67 करोड़ रुपये और ऊपरी स्तर पर 525.14 करोड़ रुपये जुटाएगा।

कब हुई थी जीपीटी हेल्थकेयर की शुरुआत

द्वारिका प्रसाद टांटिया, डॉ. ओम टांटिया और श्री गोपाल टांटिया द्वारा स्थापित जीपीटी हेल्थकेयर की शुरुआत 2000 में कोलकाता में आठ बिस्तरों वाले अस्पताल से हुई थी।

आज यह 561 बिस्तरों की कुल क्षमता के साथ 4 फुल सर्विस मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों का संचालन करता है।

कंपनी ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड, ज्यूपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड और शैल्बी लिमिटेड सहित सूचीबद्ध उद्योग साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है।

इश्यू में किसका कितना हिस्सा

इश्यू का आधा हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए, 35 फीसदी गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए और शेष 15 फीसदी खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है। निवेशक न्यूनतम 80 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 80 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं।

वित्त वर्ष 2013 में इसकी कुल आय 7.3 प्रतिशत बढ़कर 361.03 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2012 में 337.41 करोड़ रुपये थी।

जेएम फाइनेंशियल इस इश्यू का एकमात्र बुक-रनिंग लीड मैनेजर है। इक्विटी शेयरों को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।

देश में घटा चीनी का उत्पादन, इस वर्ष कुल 10 फीसदी गिरावट का अनुमान

उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन समीक्षाधीन अवधि में 6.12 मिलियन टन के मुकाबले 6.77 मिलियन टन अधिक था। उत्तर प्रदेश देश में चीनी उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। वहीं चीनी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में उत्पादन इस विपणन वर्ष के फरवरी तक घटकर 7.94 मिलियन टन रह गया जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 8.59 मिलियन टन था।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश में चीनी के उत्पादन में गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्तमान विपणन वर्ष (Marketing Year) की 15 फरवरी तक चीनी उत्पादन 2.48 फीसदी की गिरावट के साथ 22.36 मिलियन टन हो गया। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन (ISMA) के ताजा आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। एक साल पहले ही इसी अवधि में चीनी उत्पादन 22.93 मिलियन टन रहा था।

बता दें कि चीनी के लिए विपणन वर्ष की गणना अक्टूबर से सितंबर के बीच की जाती है। अपने दूसरे अनुमान में, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) ने चालू विपणन वर्ष (2023-24) में चीनी उत्पादन 10 प्रतिशत घटकर 33.05 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष में 36.62 मिलियन टन था।

ISMA ने बताया कि, चालू विपणन वर्ष में अब तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में चीनी उत्पादन में गिरावट रही।

हालांकि, उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन समीक्षाधीन अवधि में 6.12 मिलियन टन के मुकाबले 6.77 मिलियन टन अधिक था। उत्तर प्रदेश देश में चीनी उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है।

वहीं चीनी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में उत्पादन इस विपणन वर्ष के फरवरी तक घटकर 7.94 मिलियन टन रह गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 8.59 मिलियन टन था। इसी तरह, देश के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक कर्नाटक में उत्पादन 4.6 मिलियन टन से घटकर 4.32 मिलियन टन रह गया। इस विपणन वर्ष में

चीनी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में उत्पादन इस विपणन वर्ष के फरवरी तक घटकर 7.94 मिलियन टन रह गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 8.59 मिलियन टन था। इसी तरह, देश के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक कर्नाटक में उत्पादन 4.6 मिलियन टन से घटकर 4.32 मिलियन टन रह गया।

अब तक गुजरात में चीनी का उत्पादन 6,85,000 टन और तमिलनाडु में 4,50,000 टन तक पहुंच गया है।

चालू विपणन वर्ष के 15 फरवरी तक लगभग 505 कारखाने चल रहे थे, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह आंकड़ा 502 था। आईएसएमए ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में लगभग 22 कारखानों ने अपना परिचालन बंद कर दिया है।

ईडी को नहीं मिले पेटीएम पेमेंट्स बैंक में विदेशी मुद्रा उल्लंघन के सुबूत

परिवहन विशेष न्यूज

ED Probe Paytm पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले में जांच कर रही ईडी को अब तक विदेशी मुद्रा उल्लंघन के सुबूत नहीं मिले हैं। समाचार एजेंसी रायटर्स ने बताया कि जब इस संबंध में ईडी से संपर्क किया गया तो उसने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इन्कार कर दिया। RBI ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में 31 जनवरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे।

नई दिल्ली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) की जांच कर रही ईडी को अब तक विदेशी मुद्रा उल्लंघन का कोई सुबूत नहीं मिला है। जांच एजेंसी अब तक यह तय नहीं कर पाई है किसी संभावित उल्लंघन के लिए कंपनी पर कोई आरोप लगाए जाएं या नहीं।

50 प्रतिशत से अधिक गिरे Paytm के शेयर

जब इस संबंध में ईडी से संपर्क किया गया तो उसने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इन्कार कर दिया। आरबीआई (RBI) ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में 31 जनवरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। तब से पेटीएम के शेयरों में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ चुकी है। वहीं शेयरधारकों की संपत्ति करीब 3.1 अरब डालर कम हुई है।

क्यूआर कोड, साउंडबॉक्स और कार्ड मशीन पर रोक नहीं

बर्नस्टीन के विश्लेषकों ने कहा कि आरबीआई द्वारा समयसीमा विस्तार से पेटीएम पेमेंट्स बैंक खातों को आसानी से स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी और व्यापार कंपनी के क्यूआर कोड, साउंडबाक्स और कार्ड मशीनों का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

यह कंपनी के हित में एक सकारात्मक कदम है। सिटी ने भी आरबीआइ के कदम को सकारात्मक बताया है, लेकिन उसने स्टॉक पर अपनी 'सेल' रेटिंग बरकरार रखी है।

Paytm से सीख लें Fintech कंपनियां : राजीव चंद्रशेखर

समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले में बोलते हुए कहा कि इस मामले से फिनटेक कंपनियों को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नियमों का पालन कंपनियों के लिए वैकल्पिक नहीं हो सकता है, बल्कि यह एक ऐसा पहलू है जिस पर हर उद्यमी को ध्यान देना चाहिए।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड मामले को लेकर राजवी चंद्रशेखर का यह भी कहना था कि कंपनी कोई भी हो, चाहे वह भारत की हो या विदेश की, बड़ी हो या छोटी, उसे देश के कानूनों का पालन करना होगा।

भगवान शिव : माघ शुक्ल पक्ष सोमवार / सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि योग-:

"न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदो न यज्ञः।
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।।"

भगवान शिव अनादि और अनन्त हैं। सम्पूर्ण विश्व की अभिव्यक्ति हैं। इस विश्व का हर कण ही शिव है। एक से अनेक होकर एक मात्र शिव ही इस विश्वरूप में क्रीड़ा कर रहे हैं।

शास्त्रों के अनुसार शिव को महादेव इसलिए कहा गया है कि वे देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, किन्नर, गंधर्व पशु-पक्षी व समस्त वनस्पति जगत के भी स्वामी हैं।

शिव का एक अर्थ 'कल्याणकारी' भी है। शिव की अराधना से सम्पूर्ण सृष्टि में अनुशासन, समन्वय और प्रेम भक्ति का संचार होने लगता है।

इसीलिए, स्तुति गान कहता है-: हे ! देव, मैं आपकी अनन्त शक्ति को भला कैसे समझ सकता हूँ. ? अतः, हे शिव ! आप जिस रूप में भी हों उसी रूप को आपको मेरा प्रणाम। हम जितना विनम्र होंगे प्रभु उतना ही हममें प्रकट होंगे। जब भक्ति जगती है तब औदार्य आता है। जो जितना उदार है, वो प्रभु के उतना ही निकट है।

भगवान शिव के नाम का उच्चारण करने से ही दुःखों का निवारण हो जाता है। हमें भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था और विश्वास रखना चाहिये।

देवों के देव भगवान शिव सृष्टि के प्रकट देव हैं, जो भक्तों की सूक्ष्म अराधना से श्रद्धाभाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव का नाम लेते ही सभी दुःखों का नाश होता है।

माघ शुक्ल पक्ष का सोमवार व सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि जैसे श्रेष्ठ योग हैं अतः एक लोटा जल (गंगाजल मिलाकर) और कुछ विल्वपत्र-पुष्प इत्यादि लेकर भगवान भोलेनाथ का कर दीजिए जलाभिषेक।

(ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जन्म कुंडली में विद्यमान चंद्र ग्रह का दोष का भी शमन होगा।)

भगवान शिव के 108 नाम

एक जल का लोटा कुछ आक, धतूरे, विल्वपत्र अर्पण मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आइए सब मिलकर ऐसे सदाशिव भोलेनाथ के 108 नाम का जप करें- :

1- ॐ भोलेनाथ नमः
2-ॐ कैलाश पति नमः
*-ॐ भूतनाथ नमः
4-ॐ नंदराज नमः
5-ॐ नन्दी की सवारी नमः
6-ॐ ज्योतिलिंग नमः
7-ॐ महाकाल नमः
8-ॐ रुद्रनाथ नमः
9-ॐ भीमशंकर नमः
10-ॐ नटराज नमः
11-ॐ प्रलेयन्कार नमः
12-ॐ चंद्रमोली नमः
1*-ॐ डमरूधारी नमः
14-ॐ चंद्रधारी नमः
15-ॐ मलिकार्जुन नमः
16-ॐ भीमेश्वर नमः
17-ॐ विषधारी नमः
18-ॐ बम भोले नमः
19-ॐ ओंकार स्वामी नमः
20-ॐ ओंकारेश्वर नमः
21-ॐ शंकर त्रिशूलधारी नमः
22-ॐ विश्वनाथ नमः
2*-ॐ अनादिदेव नमः
24-ॐ उमापति नमः
25-ॐ गोरापति नमः
26-ॐ गणपिता नमः
27-ॐ भोले बाबा नमः
28-ॐ शिवजी नमः
29-ॐ शम्भु नमः
*0-ॐ नीलकंठ नमः
*1-ॐ महाकालेश्वर नमः
*2-ॐ त्रिपुरारी नमः
**-ॐ त्रिलोकनाथ नमः
*4-ॐ त्रिनेत्रधारी नमः
*5-ॐ बर्फानी बाबा नमः
*6-ॐ जगतपिता नमः
*7-ॐ मृत्युन्जन नमः
*8-ॐ नागधारी नमः
*9- ॐ रामेश्वर नमः
40-ॐ लंकेश्वर नमः
41-ॐ अमरनाथ नमः
42-ॐ केदारनाथ नमः
4*-ॐ मंगलेश्वर नमः
44-ॐ अर्धनारीश्वर नमः
45-ॐ नागार्जुन नमः
46-ॐ जटाधारी नमः
47-ॐ नीलेश्वर नमः
48-ॐ गलसर्पमाला नमः
49- ॐ दीनानाथ नमः
50-ॐ सोमनाथ नमः
51-ॐ जोगी नमः
52-ॐ भंडारी बाबा नमः
5*-ॐ बमलेहरी नमः
54-ॐ गोरीशंकर नमः
55-ॐ शिवाकांत नमः
56-ॐ महेश्वराए नमः
57-ॐ महेश नमः
58-ॐ ओलोकानाथ नमः
54-ॐ आदिनाथ नमः
60-ॐ देवदेवेश्वर नमः
61-ॐ प्राणनाथ नमः
62-ॐ शिवम् नमः
6*-ॐ महादानी नमः
64-ॐ शिवदानी नमः
65-ॐ संकटहारी नमः
66-ॐ महेश्वर नमः
67-ॐ रुंडमालाधारी नमः
68-ॐ जगपालनकर्ता नमः
69-ॐ पशुपति नमः
70-ॐ संगमेश्वर नमः
71-ॐ दक्षेश्वर नमः
72-ॐ घ्रेनश्वर नमः
7*-ॐ मणिमहेश नमः
74-ॐ अनादी नमः
75-ॐ अमर नमः
76-ॐ आशुतोष महाराज नमः
77-ॐ विलवकेश्वर नमः
78-ॐ अचलेश्वर नमः
79-ॐ अभयंकर नमः
80-ॐ पातालेश्वर नमः
81-ॐ धूधेश्वर नमः
82-ॐ सर्पधारी नमः
8*-ॐ त्रिलोकिनरेश नमः
84-ॐ हठ योगी नमः
85-ॐ विश्लेश्वर नमः
86- ॐ नागाधिराज नमः
87- ॐ सर्वेश्वर नमः
88-ॐ उमाकांत नमः
89-ॐ बाबा चंद्रेश्वर नमः
90-ॐ त्रिकालदर्शी नमः
91-ॐ त्रिलोकी स्वामी नमः
92-ॐ महादेव नमः
9*-ॐ गढ़शंकर नमः
94-ॐ मुक्तेश्वर नमः
95-ॐ नटेषर नमः
96-ॐ गिरजापति नमः
97- ॐ भद्रेश्वर नमः
98-ॐ त्रिपुनाशक नमः
99-ॐ निर्जेश्वर नमः
100 -ॐ किरातेश्वर नमः
101-ॐ जागेश्वर नमः
102-ॐ अबधूतपति नमः
10* -ॐ भीलपति नमः
104-ॐ जितनाथ नमः
105-ॐ वृषेश्वर नमः
106-ॐ भूतेश्वर नमः
107-ॐ बैजूनाथ नमः
108-ॐ नागेश्वर नमः।।

हर हर महादेव

गाजियाबाद में पहले तीन महीनों में रोजाना 2900 यात्रियों ने किया सफर, साहिबाबाद से मेरठ तक कब दौड़ेगी ट्रेन?

गाजियाबाद में प्रतिदिन औसतन लगभग 2900 यात्री रैपिड ट्रेन का उपयोग करते हैं। मालूम हो कि पिछले साल 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया था। वहीं फरवरी में सीएमआरएस के निरीक्षण के बाद नमो भारत ट्रेन का परिचालन मेरठ से साहिबाबाद के बीच शुरू हो सकता है। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

गाजियाबाद। फरवरी में सीएमआरएस के निरीक्षण के बाद नमो भारत ट्रेन का परिचालन मेरठ से साहिबाबाद के बीच शुरू हो सकता है। इसके लिए दिल्ली परिवहन निगम की तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

वहीं ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाजियाबाद में प्रतिदिन औसतन लगभग 2,900 यात्री रैपिड ट्रेन का उपयोग करते हैं। किसान आंदोलन के चलते ट्रेन में सफर करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। आम तौर पर रोजाना 1500 से 3000 हजार लोग इसमें यात्रा कर रहे हैं।

दो दिन बंद रही थी सेवा

बता दें कि साहिबाबाद से दुहाई तक 20 और 21 जनवरी को दो दिनों के लिए नमो भारत ट्रेन का संचालन बंद किया गया था। इन दो दिनों में दुहाई से मेरठ दक्षिण तक 25 किमी. में ट्रेन के दूसरे चरण का ट्रायल रन किया गया था। इस दौरान रूट पर सिग्नल को अपग्रेड करने और परीक्षण का काम किया गया।

मालूम हो कि पिछले साल 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया था।

वर्तमान में, पांच स्टेशन - साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो चालू हैं। आंकड़ों के अनुसार, तब से अब तक 2.79 लाख से अधिक यात्रियों ने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा का उपयोग किया है।

नमो भारत ट्रैक से ढाई लाख कीमत के केबिल चोर

मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र में निर्माणाधीन नमो भारत ट्रैक से बदमाशों ने केबिल चोरी कर लिया। चोरी हुए केबिल की कीमत करीब ढाई लाख रुपये है। मामला दर्ज कर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के नजफगढ़ के मनदीप पाठक के मुताबिक, उनकी कंपनी द्वारा मोदीनगर क्षेत्र में नमो भारत ट्रैक पर केबिल लगाने का कार्य किया जा रहा है।

11 फरवरी की रात कुछ चोरों ने साइट से केबिल चोरी कर लिया। सुबह चोरी की जानकारी हुई। मामले में एसीपी का कहना है कि ट्रैक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल कर आरोपितों की पहचान करने की कोशिश चल रही है। जल्द गिरफ्तारी कर वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा।

लक्ष्मी बस 3 और जिलों में चले

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा, भुबनेस्वर् : लक्ष्मी बस आज से 3 और जिलों सुबरनपुर, झारसुगुड़ा और कंधमाल जिलों में चलेगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वीसी के माध्यम से शुभारंभ। लक्ष्मी बस को लेकर तीन जिलों के लोग काफी उत्साहित हैं। लक्ष्मी बस आज से 3 और जिलों में चलेगी। सुबरनापुर, झारसुगुड़ा और कंधमाल जिले में लक्ष्मी बस योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री नवीन वीसी के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर लक्ष्मी योजना के तहत बसों का शुभारंभ किया। सुबरनापुर जिले के 6 ब्लॉकों के लिए 12 बसें शुरू की गयी। लक्ष्मी बस योजना को लेकर सुबरनापुर जिले के निवासियों के मन में काफी उत्साह है। इसमें विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी और अन्य स्थानीय नेता शामिल होई थी।

मोदी ने दिया है 100 दिन का लक्ष्य: केन्द्रमंत्री बिशेश्वर टुडू

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा, भुबनेश्वर : भाजपा नेता दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद दिल्ली से लौटे। दिल्ली से लौटने के बाद केंद्रीय मंत्री बिशेश्वर टुडू की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा, मोदी ने 100 दिन का लक्ष्य दिया है। कार्यकर्ता लाभार्थियों के साथ रहेंगे और मोदी का संदेश पहुंचाएंगे। मोदी का संदेश लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देगा। बूथ चलो, गांव चलो अभियान आदि के साथ भाजपा लोकानाक तक जाएगी। हर राज्य की अलग-अलग राजनीतिक स्थिति है, इसके लिए विशेष योजना होगी।

दिल्ली कूच को लेकर करमन बार्डर सहित कई जगहों पर लगाए गए नाके, जांच के बाद ही वाहने को जाने की अनुमति

किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को किए गए दिल्ली कूच के आह्वान को लेकर सोमवार को पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित करमन बार्डर पर बेरीकेड आदि लगाए गए हैं। पुलिस कर्मचारियों की एक कम्पनी तैनात की गई है। किसी भी वाहन को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही दिल्ली की तरफ जाने दिया जा रहा है।

पलवल। किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को किए गए दिल्ली कूच के आह्वान को लेकर सोमवार को पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित करमन बार्डर पर बेरीकेड आदि लगाए गए हैं। पुलिस कर्मचारियों की एक कम्पनी तैनात की गई है। किसी भी वाहन को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही दिल्ली की तरफ जाने दिया जा रहा है।

किसी भी स्थिति से निपटने के लिए डीएसपी कुलदीप सिंह व थाना प्रभारी उमर मोहम्मद कमान संभाले हुए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जगह जगह लगाई गए पुलिस नाकों पर गश्त कर रहे हैं। बिजली विभाग के एसडीओ सुरेंद्र मेहरा एवं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेश कुमार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

थाना प्रभारी उमर मोहम्मद ने बताया कि किसानों के दिल्ली कूच को लेकर ट्रैक्टरों पर सवार लोगों से पूछताछ और जांच के बाद ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर गढ़ी उमराला सड़क मार्ग स्थित उझीना ड्रेन, चमेलीवन सडक मार्ग, उमराला मोड, विजयगढ सहित कई अन्य जगहों पर पुलिस नाके लगाए गए हैं। जहां से निकलने वाले सभी वाहनों की जांच पड़ताल के बाद ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है।

कानून एवं व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

इस बारे में पुलिस अधीक्षक डॉ. अंशु सिंगला ने बताया कि जिले में कानून एवं व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी के बहकावे या उकसावे में आकर कानून व्यवस्था को ना बिगाडे और क्षेत्र में शांति व कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम

उन्होंने कहा कि पुलिस किसी भी प्रकार की अप्रिय परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। किसी भी नागरिक को अफवाहों पर ध्यान देकर माहौल को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अमन-चैन व शांति का माहौल है। कोई भी नागरिक या संगठन यदि शांति व्यवस्था बाधित करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अफवाहों पर ध्यान ना देने को कहा गया

उन्होंने आह्वान किया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। पुलिस प्रशासन की सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। अगर कोई भी व्यक्ति गलत अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि आपसी भाईचारे को बनाएं रखें।

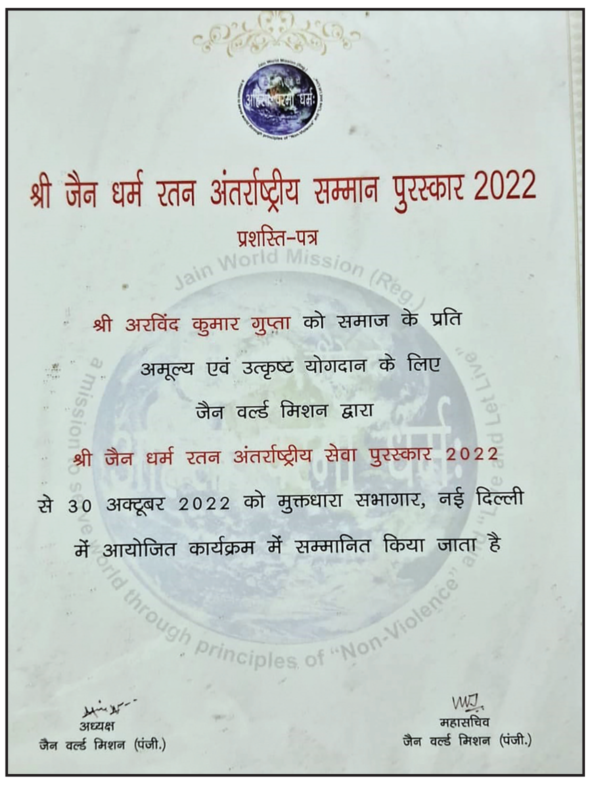
श्री जैन धर्म रतन अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार 2022

प्रशस्ति-पत्र

श्री अरविंद कुमार गुप्ता को समाज के प्रति अमूल्य एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए जैन वर्ल्ड मिशन द्वारा श्री जैन धर्म रतन अंतर्राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार 2022 से 30 अक्टूबर 2022 को मुक्तधारा सभागार, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाता है

अध्यक्ष
जैन वर्ल्ड मिशन (पंजी.)

महासचिव
जैन वर्ल्ड मिशन (पंजी.)

दिल्ली एयरपोर्ट पर एक-दूसरे काफी करीब आए इंडिगो के दो विमान, थम गई थी सासें

राष्ट्रीय राजधानी के आईजीआई एयरपोर्ट (IGI Airport Delhi) से उड़ान भर चुके दो विमानों के बीच तय मानक दूरी से कम दूरी के बीच उड़ान भरने का मामला सामने आया है। एएआईबी (एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इंविस्टिगेशन ब्यूरो) इस पूरी घटना की जांच में जुटी है। दोनों विमान इंडिगो (Indigo Flight) के हैं। इनमें से एक विमान हैदराबाद तो दूसरा विमान रायपुर की उड़ान पर था।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के आईजीआई एयरपोर्ट (IGI Airport Delhi) से उड़ान भर चुके दो विमानों के बीच तय मानक दूरी से कम दूरी के बीच उड़ान भरने का मामला सामने आया है। एएआईबी (एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इंविस्टिगेशन ब्यूरो) इस पूरी घटना की जांच में जुटी है। दोनों विमान इंडिगो (Indigo Flight) के हैं।

इनमें से एक विमान हैदराबाद तो दूसरा विमान रायपुर की उड़ान पर था। इंडिगो (Indigo Airline) ने इस पूरे प्रकरण पर फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। मामला पिछले वर्ष 17 नवंबर का है। तय मानक के अनुसार उड़ान के दौरान दो विमानों के बीच वर्टिकल (लंबवत) दूरी कम से कम एक हजार फीट की होनी चाहिए।

किससे हुई गलती

लेकिन इस मामले में यह दूरी एक हजार से कम हो गई। एक बार तो यह दूरी 400 फीट तक पहुंच गई। यह गलती एटीसी के स्तर पर हुई या फिर पायलट के स्तर पर अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया

बताया जा रहा है कि रायपुर जा रहे विमान को एटीसी ने उड़ान के दौरान 8 हजार फीट की ऊंचाई तक जाने को कहा, लेकिन विमान ने सीध में उड़ान न भरकर विमान का रुख दूसरे रनवे की ओर कर लिया। समस्या तब गंभीर हो गई जब दूसरे रनवे से हैदराबाद के लिए विमान ने उड़ान भरी। विमान की दिशा कैसे बदली इसे लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023